# घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 91- शनिवार 31- जनवरी 2026,पृष्ठ - 8+4 मूल्य 4 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028


# महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि

# प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी

## भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : पीयूष गोयल

**नई दिल्ली,30 जनवरी 2026।** केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में आयोजित आईसीएआई वर्ल्ड फोरम ऑफ अकाउंटेंट्स कार्यक्रम में कहा कि भारत का वस्तु और सेवा निर्यात इस वर्ष भी लगातार बढ़ रहा है। 'मुझे विश्वास है कि कड़ी मेहनत के चलते हम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।'

### 38.5 अरब डॉलर पर पहुंचा भारत का निर्यात

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष दिसंबर में देश का वस्तु निर्यात 1.87 प्रतिशत बढ़कर 38.5 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। वहीं, आयात 8.7 प्रतिशत बढ़कर 63.55 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान देश का वस्तु निर्यात 2.44 प्रतिशत बढ़कर 330.29 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि देश का वस्तु और सेवा निर्यात 2025-26 में 850 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर सकता है, जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा 825 अरब अमेरिकी डॉलर था।

## वकील के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द,कोर्ट ने कहा...पेशेवर काम को डराना-धमकाना नहीं कहा जा सकता

**नई दिल्ली,30 जनवरी 2026।** सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को शुक्रवार को रद्द कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि वकील के सलाह देने जैसे पेशेवर काम को डराना या धमकाना नहीं कहा जा सकता। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि बिना ठोस सबूत के अस्पष्ट और बेबुनियाद आरोप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध नहीं बनाते। शीर्ष कोर्ट ने यौन अपराध से बच्चों का का संरक्षण (पॉक्सो) मामले में आरोपी के चाचा,वकील बेरी मनोज के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। बेंच ने गौर किया कि पीड़िता ने जो बयान दिया था, उसमें बाद में बदलाव आया। पहला बयान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत पुलिस के समक्ष दिया गया था। दूसरा बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई वकील अपने पेशेवर काम में होता है, तो उसे डराने-धमकाने के तौर पर नहीं देखा जा सकता और इस मामले में यह जरूरी तथ्य (कि वकील धमकी दे रहा था) पूरी तरह गायब था।

## अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मौत की जांच सीआईडी को सौंपी गई

**मुंबई,30 जनवरी 2026।** महाराष्ट्र सरकार ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मौत की जांच शुक्रवार को सीआईडी को सौप दी। यह जानकारी गृह विभाग के सूत्रों ने दी। 28 जनवरी को बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने आज इस मामले की सीआईडी जांच का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने हादसा ग्रस्त स्थल को प्रतिबंधित घोषित कर दिया है और सीआईडी टीम मौके पर पहुंच कर जांच शुरु कर दी है। सीआईडी की टीम बारामती हवाई अड्डे पर सुरक्षा खामियों और बुनियादी ढांचे के मुद्दों की जांच करेगी। इस मामले को शुरू में पुणे ग्रामीण पुलिस संभाल रही थी। सरकार ने पुणे ग्रामीण पुलिस को मामला और अब तक जुटाई गई जानकारी राज्य सीआईडी को सौंपने के लिए कहा है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था।

## राहुल गांधी बोले...राष्ट्रपिता का मंत्र था सत्ता से बड़ी सत्य की ताकत

**नई दिल्ली,30 जनवरी 2026।** राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर-राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा,जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधारस्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। राहुल गांधी ने लिखा कि राष्ट्रपिता ने हमें मूलमंत्र दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है।

### जयराम रमेश का बीजेपी सांसद पर तंज

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बिना नाम लिए पूर्व जज और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय की महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को लेकर की गई टिप्पणी की आलोचना की। जयराम रमेश ने लिखा कि महात्मा गांधी की हत्या से दो दिन पहले जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा था। इसके कुछ महीनों बाद, 18 जुलाई 1948 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा था। इन दोनों पत्रों में स्वयं को राष्ट्रवाद का स्वघोषित संरक्षक बताने वालों पर बेहद गंभीर आरोप हैं। यह सोचकर हैरानी होती है कि उसी विचारधारा से जुड़े एक लोकसभा सांसद,जिन्हें प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने यह कहा कि वह गांधी और गोडसे में से किसी एक को नहीं चुन सकते। उनकी यह मानसिकता बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में 'सरदार पटेल कॉरस्पोंडेंस (1945-1950)' किताब के पन्नों के साथ 30 जनवरी 1948 की रात को ऑल इंडिया रेडियो पर जवाहरलाल नेहरू के भाषण का लिंक भी साझा किया।

### सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच हैं। वह सोच जिसे कभी एक साम्राज्य ने, कभी एक नफरत की विचारधारा ने और कभी अहंकारी सत्ता ने मिटाने की असफल कोशिश की। मगर राष्ट्रपिता ने हमें आजादी के साथ यह मूलमंत्र दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है। हिंसा व भय से बड़े अहिंसा और साहस। यह सोच मिट नहीं सकती, क्योंकि गांधी भारत की आत्मा में अमर हैं। बापू को उनके शहीदी दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि।

### शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है दिन

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि हर साल 30 जनवरी को मनाई जाती है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देशभर में शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

## हर स्कूल में लड़कियों को सैनेटरी पैड मिले लड़के-लड़कियों के अलग टॉयलेट हों : सुप्रीम कोर्ट

**नई दिल्ली,30 जनवरी 2026।** सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनेटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में दिव्यांग-अनुकूल (डिसेबल-फ्रेंडली) टॉयलेट बनाए जाएं। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने क्लास 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में केंद्र सरकार की मेंस्ट्रुअल हाइजिन पॉलिसी को पूरे भारत में लागू करने पर यह आदेश सुनाया। अगर स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं हैं तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 (बराबरी का अधिकार) का

उल्लंघन है। अगर लड़कियों को सैनिटरी पैड नहीं मिलते। तो वे लड़कों की तरह बराबरी से पढ़ाई और गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पातीं। मासिक धर्म के दौरान सम्मानजनक सुविधा मिलना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) का हिस्सा है। अगर लड़कियों को उचित सुविधा नहीं मिलती तो उनकी गरिमा और निजता प्रभावित होती है।

### कोर्ट ने कहा...लड़कियों के शरीर को बोझ के रूप में देखा जाता है...

यह आदेश सिर्फ कानूनी व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए नहीं है। यह उन क्लासरूम के लिए भी है, जहां लड़कियां मदद मांगने में झिझकती हैं। यह उन टीचर्स के लिए है, जो मदद करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण बंधे हुए हैं। यह उन माता-पिता के लिए भी है, जो शायद यह नहीं समझ पाते कि उनकी चुप्पी का क्या असर पड़ता है। यह समाज के लिए भी है, ताकि प्रगति का पैमाना इस बात से तय हो कि हम अपने सबसे कमजोर वर्ग की कितनी सुरक्षा करते हैं। हम हर उस बच्ची तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जो स्कूल में अबसेंट होने की शिकार बनी, क्योंकि उसके शरीर को बोझ की तरह देखा गया जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है।

## भारत में निपाह वायरस के संक्रमण का जोखिम बहुत कम : डब्ल्यूएचओ

**नई दिल्ली,30 जनवरी 2026।** विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत-बांग्लादेश के जंगलों में चमगादड़ों की मौजूदगी के बावजूद पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के संक्रमण के जोखिम को मध्यम दर्जे का बताया है। अलबत्ता,राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक जोखिम का स्तर निम्न है। इस समय इस संक्रमण के इंसानों से इंसानों में फैलने के अब तक कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। डब्ल्यूएचओ

ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के संक्रमण के दो मामलों की पुष्टि की है। संक्रमित दोनों व्यक्ति 25 वर्ष की आयु के हैं, जिनमें एक महिला और एक पुरुष है। ये दोनों व्यक्ति उत्तरी 24 परगना जिले के एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं। इन दोनों व्यक्तियों में विगत दिसंबर के अंतिम दिनों में संक्रमण के आरम्भिक लक्षण विकसित हुए थे जो बहुत तेजी से तंत्रिका संबंधी जटिलताओं में तब्दील हो गए थे। इन दोनों संक्रमित व्यक्तियों को जनवरी के आरम्भिक दिनों में चिकित्सकीय एकांतवास में रखा गया था। संक्रमण के मामलों का पता चलने के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित एक व्यापक कार्रवाई शुरू की गई।

इन दो संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए कुल 196 व्यक्तियों की पहचान निर्धारित की गई। उनका पता लगाया गया और उन्हें स्वास्थ्य निगरानी में रखा गया और उनके परीक्षण किए गए। इन सभी लोगों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं देखे गए।

## योगी 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें,गाय को गोमाता घोषित करें,वरना मानेंगे सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ पहना : अविमुक्तेश्वरानंद

**वाराणसी,30 जनवरी 2026।** प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा...मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया। मैंने वह दे दिया। मेरे प्रमाण सच्चे थे,इसलिए उन्हें

मानना पड़ा। अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। उन्होंने कहा...हम आपको 40 दिन का समय दे रहे। इन दिनों में आप गो-भक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं दे पाते,तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू,कालनेमि,पाखंडी और ढोंगी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री और जगदुरु रामभद्राचार्य घेराबंदी करके गोहत्या बंदी की मांग करने वालों पर तरह-तरह के हमले कर रहे। अगर आप सच में हिंदू हैं,तो गो-माता को राज्य माता घोषित करें। यूपी से गोमांस का निर्यात बंद करें, नहीं तो गैर हिंदू घोषित कर देंगे।

### लखनऊ में जुटेंगे संत,तय करेंगे कौन असली हिंदू...

शंकराचार्य ने कहा...10-11 मार्च को लखनऊ में सभी संत-महंत और आचार्य एकत्र हों। वहां यह तय किया जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू हृदय सम्राट है और किसे छद्म हिंदू या नकली हिंदू घोषित किया जाना चाहिए।

### अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश करेंगे...

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा...अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। जितने भी हिंदू हैं, उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। यह छल खुद को साधु,योगी,संत और भगवाधारी कहने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी द्वारा किया जा रहा। माघ मेला छोड़ने पर शंकराचार्य ने कहा...माफी मांगने का भी एक तरीका होता है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। प्रशासन हमें लालच दे रहा था कि आप ऐसे नहा लीजिए,आपके ऊपर फूल बरसा देंगे। अगले साल के लिए चारों शंकराचार्यों के लिए प्रोटोकॉल बना देंगे,लेकिन हमने नकार दिया। हमने कहा कि जिन संन्यासियों पर आपने लाठी बरसाई, उनसे माफी मांगिए। अगर वे क्षमा कर दें,तो ठीक,लेकिन इस सब के लिए प्रशासन आगे नहीं आया।

## राहुल ने स्कार्फ न पहनकर नॉर्थईस्ट का अपमान किया कांग्रेस के शासन में असम की डेमोग्राफी बदली : शाह

**गुवाहाटी,30 जनवरी 2026।** गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नॉर्थईस्ट का अपमान करने का आरोप लगाया। असम के खानिकर परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर विदेशियों सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने सम्मान के प्रतीक के रूप में स्कार्फ पहना था,लेकिन राहुल ने इनकार कर दिया था। शाह ने आगे कहा कि राहुल गांधी जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब तक बीजेपी सत्ता में है। हमारी पार्टी नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। गृह मंत्री ने कहा...मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी ने असम को बंदूकें,गोलियां,संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा क्या दिया है। शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठ को 'अपने वोट बैंक की राजनीति के हथियार' के रूप में इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।

### शाह बोले- असम में डेमोग्राफिक ट्रेंड बदलने पर जोर

शाह ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान असम की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई। घुसपैठियों की आबादी शून्य से बढ़कर 64 लाख हो गई और सात जिलों में घुसपैठिए बहुमत में हो गए। मोदी सरकार राज्य में

### शाह ने कहा...असम से राज्यसभा सांसद रहे मनमोहन सिंह भी काम नहीं कर पाए...

केंद्रीय गृह मंत्री ने असम में घुसपैठियों को बसने से रोकने में मिसिंग समुदाय की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा...घुसपैठ को रोकना मिसिंग समुदाय की जिम्मेदारी है। आपको बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। डिब्रूगढ़ और धेमाजी को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल के बारे में बात करते हुए,शाह ने कहा कि यह पूरी दुनिया के सामने भारत की प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने कहा...हालांकि,भारत में बहुत कम लोग जानते हैं कि बोगीबील पुल मिसिंग समुदाय के मेरे भाइयों और बहनों की कड़ी मेहनत और पसीने से बनाया गया था। आज,यह पुल देश भर में और विश्व स्तर पर एक नए भारत की सोच का एक शक्तिशाली प्रतिनिधित्व बन गया है।' केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि असम से राज्यसभा सांसद मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन यह पुल अधूरा ही रहा। असम के लोगों ने मोदी जी पर भरोसा किया।

डेमोग्राफिक ट्रेंड को उलटने के लिए विभिन्न तरीकों से काम कर रही है। उन्होंने कहा, अगर आप असम में घुसपैठ रोकना चाहते हैं, तो तीसरी बार बीजेपी सरकार चुनें और अवैध प्रवासियों के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के हाथों को मजबूत करें। असम में दो बीजेपी राज्य सरकारों ने घुसपैठियों के अतिक्रमण से 1.26 लाख एकड़ जमीन मुक्त कराई है।

### शाह बोले...असम की चाय यूरोपीय देशों में भेजी जाएगी

शाह ने यह भी कहा... कि कांग्रेस ने असम और उसके चाय उद्योग को बदनाम करने के लिए एक टूलकिट जारी किया था। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते से यह सुनिश्चित होगा कि असम की चाय यूरोपीय देशों में बिना किसी टैरिफ के भेजी जाएगी। शाह ने कहा कि बीजेपी ने पिछले चुनावों में वादा किया था कि उसकी सरकार असम को बाढ़ मुक्त बनाएगी। इस दिशा में कदम 2026 के चुनावों से पहले ही उठाए जा चुके हैं। उन्होंने असम के मतदाताओं से अपील की कि' विकास, शांति, सुरक्षा, औद्योगिक और कृषि प्रगति सुनिश्चित करने और असम को घुसपैठ और बाढ़ से मुक्त बनाने के लिए लगातार तीसरी बार बीजेपी को चुनें।

## मनरेगा की बहाली तक जारी रहेगा आंदोलन : कांग्रेस

**नई दिल्ली,30 जनवरी 2026।** कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की पुनर्बहाली की मांग को लेकर शुक्रवार को यहां अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय से गांधी स्मृति तक विरोध मार्च निकाला। पार्टी नेताओं ने ऐलान किया कि जब तक सरकार मनरेगा को बहाल नहीं करती,तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा।कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन के तहत आयोजित इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने उस मनरेगा को खत्म किया है जो पंचायतों को सशक्त करने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सीधे पैसा पहुंचाने का जरिया था।उन्होंने कहा कि मनरेगा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अधिनियम था जो सितंबर 2005 को सर्वसम्मति से पारित हुआ था। इसको बनाने में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का महत्वपूर्ण योगदान था। मनरेगा कानून संवैधानिक हक था, लोगों के पास रोजगार की कानूनी गारंटी थी। इस कानून से पंचायतें मजबूत हुईं। हर परिवार को पहली बार डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाया गया लेकिन ये कानून रद्द कर दिया गया,क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं चाहते हैं कि महात्मा गांजी से जुड़ा हुआ ये कानून ज्यादा समय तक चले। वो नहीं चाहते हैं

कि लोगों को उनका हक मिले। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं,बल्कि देश के करोड़ों गरीबों के रोजगार और सम्मान की गारंटी है। कांग्रेस शासन में गरीबों को अपने गांव में रहकर इज्जत की रोटी कमाने का हक मिला था,जिससे ग्रामीण भारत का विकास हुआ लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस व्यवस्था को चोट पहुंचाई। यह लड़ाई हर उस किसान और मजदूर की है जिसका हक छीना जा रहा है। कांग्रेस के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जो सरकार देश के अन्नदाता और श्रमशक्ति का अपमान करती है वो सत्ता में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। कांग्रेस ने एलान किया कि जब तक सरकार मनरेगा को बहाल नहीं करती,आंदोलन जारी रहेगा।

## संपादकीय



# श्रम उत्पादकता में सुधार का समय

**ये सुधार एक सरल,लचीले और समावेशी श्रम बाजार की दिशा में निर्णायक परिवर्तन के प्रतिनिधि प्रतीत होते हैं और यदि इन्हें सही ढंग से लागू किया जाए तो ये निश्चित रूप से नौकरियों में औपचारिकीकरण की प्रि या को गति देंगे,उत्पादकता में सुधार करेंगे और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बड़े उद्यमों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा आवरण का कवच तैयार करते हुए अंततः जीडीपी वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को बढ़ाएंगे...**

उत्पादक क्षमता में विस्तार ही आर्थिक वृद्धि का आधार है। यह उत्पादकता पूंजी,तकनीक और श्रम बल जैसे पहलुओं के मिश्रण पर निर्भर करती है। इसमें भी श्रम एक महत्वपूर्ण अवयव है। श्रम के माध्यम से अन्य संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित होता है। श्रम बल के उचित योगदान के अभाव में पूंजी और तकनीक जैसे अन्य संसाधन भी अभीष्ट की पूर्ति में पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं रह जाते।

उत्पादक क्षमताओं की पड़ताल करें तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आइएलओ के अनुसार भारत की श्रम उत्पादकता प्रति कार्य घंटे आठ अमेरिकी डालर है। जबकि इसी पैमाने पर विश्व में सिरमौर लक्जमबर्ग की प्रति घंटे श्रम उत्पादकता 146,आयरलैंड की 143, नार्वे की 93 और सिंगापुर की 74 डालर है। भारत की श्रम उत्पादकता जी-20 देशों में सबसे कम है। यहां तक कि मध्यम आय और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले मेक्सिको, ब्राजील जैसे देश भारत की तुलना में प्रति कार्य घंटे कई गुना अधिक उत्पादन करते हैं।

भारत सप्ताह में 46-48 घंटे काम करने वाले देशों में शीर्ष पर है, जो चीन और जापान से भी अधिक है। इसके परिणामस्वरूप बहुत कम वेतन के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद सीमित प्रति श्रमिक उत्पादन के कारण नुकसान उठाने के लिए मजबूर है। भारत इस मोर्चे पर बांग्लादेश,वियतनाम और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कम प्रतिस्पर्धी है। इस स्थिति को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने बीते नवंबर में श्रम सुधारों की दिशा में कदम उठाए हैं। देश में पहले 29 श्रम कानून थे,जो जटिलताओं से भरे थे। औपनिवेशक कार्यसंस्कृति से ओतप्रोत ये कानून समय के अनुरूप सुसंगत भी नहीं हो पा रहे थे। इनमें 1436 प्रविधान,181 फार्म,आठ अलग-अलग पंजीकरण और 31 रिपोर्टिंग कसौटियां थीं। इसने जहां व्यापार सुगमता की राह बाधित की तो श्रमिकों को अपेक्षित सुरक्षा आवरण से भी वंचित बनाए रखा। अब इन 29 कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेट दिया गया है।

# परमाणु बम फटने खतरे की आहट

संजय गोस्वामी,
अनुशक्तिनगर, मुंबई

फिलहाल दुनिया में 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। फेडरेशन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स की 2025 की स्टेटस ऑफ द वर्ल्डस न्यूक्लियर फोर्सेज रिपोर्ट के अनुसार, इन देशों के पास लगभग 12,331 परमाणु हथियार हैं,जिनमें से 9,600 से ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री स्टॉक में हैं। हालांकि यह शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों वाले देशों के पास मौजूद लगभग 70,000 हथियारों की तुलना में काफी कम है,लेकिन उम्मीद है कि अगले दशक में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ेगी और आज की सेनाएं कहीं ज़्यादा सक्षम हैं।

रूस के पास सबसे ज़्यादा कन्फर्म परमाणु हथियार हैं,जिनके पास 5,500 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर आता है,जिसके पास 5,044 परमाणु हथियार हैं,जो अमेरिका और 5 अन्य देशों तुर्की,इटली,बेल्जियम,जर्मनी और नीदर लैंड में रखे गए हैं। अकेले इन 2 देशों के पास दुनिया के लगभग 90त्न परमाणु हथियार हैं। उत्तर कोरिया और इज़राइल के पास कुल हथियारों की संख्या कन्फर्म नहीं है। हालांकि,यह अनुमान लगाया गया है कि उत्तर कोरिया के पास 40-50 अलग-अलग हथियार बनाने के लिए पर्याप्त फिसाइल मटीरियल है, जबकि इज़राइल के पास 200 तक हथियार बनाने के लिए मटीरियल है,जिसमें अनुमानित 90 मौजूदा हथियार शामिल हैं।

एक परमाणु हथियार लाखों लोगों को मार सकता है,जिसके स्थायी और विनाशकारी मानवीय और पर्यावरणीय परिणाम होंगे। अकेले न्यूयॉर्क पर सिर्फ़ 1 परमाणु हथियार गिराने से अनुमानित 583,160 लोगों की मौत हो जाएगी।

कुल मिलाकर,चीन,फ्रांस,भारत, इज़राइल,उत्तरकोरिया,पाकिस्तान, रूस,यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 12,300 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं,जिनमें से ज़्यादातर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु हथियार से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। बत्तीस अन्य देश भी इस समस्या का हिस्सा हैं, जिनमें से छह देशों में परमाणु हथियार रखे गए हैं, और 28 अन्य देश उनके इस्तेमाल का समर्थन करते हैं।

एक सामरिक परमाणु हथियार कोई भी ऐसा हथियार है जिसे रूसी हथियार नियंत्रण समझौतों के तहत रणनीतिक के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया गया है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि रूस के पास अभी 1,912 नॉन-स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड हैं,और अमेरिका के पास 200 नॉन-स्ट्रेटेजिक वॉरहेड हैं,जिनमें से 100 पाँच यूरोपीय देशों में तैनात हैं। हालांकि इन्हें अक्सर छोटे या कम ताकत वाले न्यूक्लियर हथियार कहा जाता है,लेकिन इन वॉरहेड की विस्फोटक क्षमता 300 किलोटन तक हो सकती है,जो यूक्रेन बीते करीब 33 महीने से रूस के साथ युद्ध में है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और उसके कई हिस्सों पर कब्जा कर लिय है। है।

**कीव:-** रूस के साथ भीषण युद्ध में उलझा यूक्रेन करीब तीन दशक पहले, 1991 में दुनिया के तीसरा सबसे बड़े परमाणु हथियारों के जखीरे का मालिक था। यूक्रेन ने एक बहुराष्ट्रीय समझौते के तहत अपने सभी परमाणु हथियार खत्म कर लिए। यूक्रेन को इस समझौते में परमाणु निरस्त्रीकरण के बदले सुरक्षा गारंटी मिली थी। हालांकि ये सुरक्षा गारंटी तब टूट गई, जब 2014 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के क्रीमिया पर आक्रमण करते हुए कब्जे कर लिया। इससे समझौता और सुरक्षा गारंटी दोनों खत्म हो गए। रूस और यूक्रेन में फरवरी, 2022 से एक बार फिर युद्ध छिड़ा हुआ है। पुतिन लगातार परमाणु हमले की धमकियां दे रहे हैं तो यूक्रेन के पास अब कोई परमाणु हथियार नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या 1991 में परमाणु हथियार छोड़ने के लिए मान जाना यूक्रेन की बड़ी भूल थी और इसी ने उस पर रूस के हमले का रास्ता साफ किया। यूक्रेन ने ऐसा ना किया होता तो शायद उस पर हमला ना होता इसलिए परमाणु ऊर्जा को हमें या तो बहुत ही सोच समझकर ही क़ोई निर्णय लेना चाहिए.अब न्यूज़ में अमेरिका और ईरान के टकराव में परमाणु बम की आहट सुनाई दे रही है अतः अब शांति से काम लेना चाहिए. हिरोशिमा को तबाह करने वाले बम से 20 गुना ज़्यादा है। अगस्त 1945 को, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया पहला परमाणु बम (लिटिल बॉय) इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक है। सुबह 8:15 बजे हुए इस हमले में लगभग 1,40,000 लोग तुरंत या उसके बाद मारे गए,जिसने शहर के 80 प्रतिशत हिस्से को राख कर दिया अब ऐसा लग रहा है कि पुनः परमाणु बम से खतरा मंडराने लगा है।

# शिक्षा में समता या नई असमानता:यूजीसी नियमों पर न्यायिक विराम

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली-92

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नाम पर लागू किए गए नए नियमों ने देश के शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में एक बार फिर गहरी हलचल पैदा कर दी है। जिस नीति को'समता','समान अवसर' और 'समावेशी शिक्षा'की भावना से जो कर प्रस्तुत किया गया,वह व्यवहार में आते ही एक वर्ग विशेष के तीव्र विरोध, व्यापक असंतोष और सामाजिक तनाव का कारण बन गई। स्थिति इतनी विकट हुई कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर इन नियमों पर अंतरिम रोक लगानी पड़ी। यह रोक न केवल सरकार की नीति-निर्माण प्रक्रिया पर एक प्रश्नचिह्न है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण और असंतुलित प्रयोग देश को किस दिशा में ले जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप किसी नीति के समर्थन या विरोध का सीधा निर्णय नहीं है,बल्कि यह एक संवैधानिक चेतावनी है कि समानता के नाम पर लागू किए गए नियम यदि अस्पष्ट हों,दुरुपयोग की संभावना रखते हों और सामाजिक सौहार्द को बाधित करते हों,तो वे न्यायिक समीक्षा से परे नहीं रह सकते। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह माना कि यूजीसी के नए नियमों में स्पष्टता का अभाव है और यही अस्पष्टता उन्हें विवादास्पद बनाती है। यह रोक सरकार को आत्ममंथन का अवसर देती हैकृएक ऐसा अवसर जिसे राजनीतिक टकराव के बजाय सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि जो सरकार बार-बार'सबका साथ,सबका विकास,सबका विश्वास' की बात करती रही है,वह शिक्षा संस्थानों जैसे विचार-निर्माण के केंद्रों में ऐसे नियम क्यों लाई, जिनसे जातिगत पहचान और वर्गीय विभाजन की रेखाएँ और गहरी होने की आशंका पैदा हो गई। भारत का सामाजिक इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि जाति के नाम पर की गई किसी भी नीति ने, चाहे उसका उद्देश्य कितना ही कल्याण कारी क्यों न रहा हो,समाज को भीतर ही भीतर विभाजित किया है। आरक्षण जैसी संवैधानिक व्यवस्था सामाजिक न्याय के लिए लाई गई थी,लेकिन इसके लंबे प्रयोग ने देश को ऐसे घाव भी दिए हैं,जिनका उपचार आज तक पूर्ण रूप से नहीं हो सका। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत आधार को और उभारने वाली किसी भी पहल को लेकर स्वाभाविक रूप से आशंका उत्पन्न होती है।

शिक्षा संस्थान केवल डिग्री बांटने की फैक्ट्रियां नहीं होते,वे समाज की दिशा तय करने वाली प्रयोगशालाएं होते हैं। यहां तैयार होने वाला छात्र केवल नौकरीपेशा व्यक्ति नहीं,बल्कि भविष्य का नागरिक होता है। यदि यही परिसर अविश्वास,वर्ग-संघर्ष और परस्पर शंका के केंद्र बन जाएं,तो इसका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता,बल्कि वह सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करता है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर उठा विरोध इसी आशंका का प्रकटीकरण है। यह भी विचारणीय है कि समानता और समता के बीच का अंतर नीति-निर्माण में किस हद तक समझा गया। समानता का अर्थ है सबके साथ एक जैसा व्यवहार, जबकि समता का अर्थ है परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित अवसर देना। यदि समता के नाम पर ऐसे प्रावधान किए जाएं जो एक नए प्रकार की असमानता को जन्म दें, तो वह नीति अपने उद्देश्य से भटक जाती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसी बिंदु की ओर संकेत करती है कि नियमों का उद्देश्य भले ही सकारात्मक रहा हो,लेकिन उनकी संरचना और भाषा ने विवाद और भ्रम को जन्म दिया।

यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग तेजी से हावी होता गया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसे अपने-अपने हितों के चश्मे से देखना शुरू कर दिया, वोट बैंक की राजनीति से इसे देखा जाने लगा जबकि यह विषय मूलतः शिक्षा सुधार और सामाजिक संतुलन से जुड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई अवसरों पर यह कहते रहे हैं कि शिक्षा को राजनीति से मुक्त रखा जाना चाहिए और नीतियां दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यूजीसी द्वारा बनाए गए इन नियमों में उस दूरदर्शिता और संतुलन का अभाव क्यों दिखा? लगता है कि यूजीसी ने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे इसे लागू कर दिया,यदि यूजीसी ने व्यापक संवाद, सभी पक्षों से परामर्श और संभावित दुरुपयोग की आशंकाओं का पूर्व आकलन किया होता,तो शायद यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। नीति बनाते समय केवल कानूनी वैधता पर्याप्त नहीं होती,सामाजिक स्वीकार्यता और नैतिक संतुलन भी उतने ही आवश्यक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश के माध्यम से यही संकेत दिया है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी बदलाव से पहले उसके दूरगामी प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

नए नियमों की सबसे बड़ी कमजोरी एवं त्रासदी यही रही कि वे आरक्षित और सामान्य वर्गों को एक-दूसरे के सामने खड़ा करके विद्रोह एवं विरोध में खड़ा कर दिया। यह विभाजनकारी प्रवृत्ति न केवल शिक्षा के वातावरण को दूषित करती है,बल्कि उस राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को भी कमजोर करती है, जिसकी बात हम संविधान में करते हैं। किसी भी नीति का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह समाज को जो ती है या तोड़ती है। यदि वह अविश्वास और टकराव को बढ़ावा देती है, तो उस पर पुनर्विचार अनिवार्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक सुधार का अवसर है-सरकार,यूजीसी और समूचे शैक्षिक तंत्र के लिए। यह समय है कि भावनाओं और राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठकर एक ऐसी नीति बनाई जाए,जो वास्तव में समान अवसर सुनिश्चित करे,लेकिन बिना किसी नए विभाजन को जन्म दिए। शिक्षा में सुधार का अर्थ समाज को आगे ले जाना है, न कि पुराने घावों को फिर से कुरेदना। देश को ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो प्रतिभा को जाति से ऊपर रखे,अवसर को पहचान से मुक्त करे और परिसरों को संघर्ष का नहीं, संवाद का केंद्र बनाए। सुप्रीम कोर्ट की यह रोक उसी दिशा में एक संकेत है। अब यह सरकार और यूजीसी की जिम्मेदारी है कि वे इस संकेत को समझें,आत्मावलोकन करें और ऐसे नियम गढ़े जो वास्तव में भारत की समावेशी,संतुलित और भविष्यद्रष्टा संरचना के अनुरूप हों। यदि इस अवसर को भी राजनीतिक स्वार्थ की भेंट चढ़ा दिया गया,तो यह केवल एक नीति की विफलता नहीं होगी,बल्कि उस विश्वास की भी हार होगी,जो जनता ने शिक्षा सुधारों से जोड़ रखा है।

# मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित मामलों की भयावह स्थिति पूरे देश की न्याय व्यवस्था के सामने गहरे संकट



सुभाष बुड़ावन वाला
रतलाम,मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित मामलों की भयावह स्थिति केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था के सामने खड़े गहरे संकट का प्रतीक है,जहां न्याय की अवधारणा समय के बोझ तले दबती जा रही है और आम नागरिक के लिए शीघ्र न्याय एक नारा बनकर रह गया है। जब 4 लाख 80 हजार से अधिक प्रकरण लंबित हों और मौजूदा 42 न्यायाधीशों के साथ उन्हें निपटाने में चार दशक से अधिक समय लगने का आकलन सामने आए,तो यह साफ हो जाता है कि समस्या केवल संख्या की नहीं,बल्कि सोच, संरचना और संसाधनों की है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39-ए राज्य को यह जिम्मेदारी देता है कि हर नागरिक को समान और प्रभावी न्याय मिले, लेकिन यदि फैसला आने में पीढ़ियां गुजर जाएं,तो यह अधिकार व्यवहार में निष्प्रभावी हो जाता है। आज देश की आबादी 140 करोड़ के पार है,लेकिन न्यायालयों और न्यायाधीशों की संख्या उस अनुपात में 50 प्रतिशत से भी कम है,नतीजा यह कि अदालतें फाइलों के पहाड़ में दबती जा रही हैं और



न्यायाधीशों पर असहनीय कार्यभार बढ़ता जा रहा है। एरियर कमेटी की रिपोर्ट यह स्पष्ट कर चुकी है कि नियुक्तियों में देरी लंबित मामलों का सबसे बड़ा कारण है,फिर भी वर्षों से स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, जो शासन और प्रशासन की उदासीनता को उजागर करता है।

केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना ही समाधान नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की भी उतनी ही आवश्यकता है, जहां हाइब्रिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक की मदद से व्यवस्था को तेज,पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग केस मैनेजमेंट,तारीखों के अनावश्यक टलने पर रोक, समान प्रकृति के मामलों की पहचान,रिसर्च असिस्टेंस और प्रारंभिक स्क्रीनिंग जैसे कार्यों में किया जा सकता है,जिससे न्यायाधीशों का समय बचे और वे निर्णय की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दे सकें। इसके साथ ही ई-कोर्ट, पेपरलेस फाइलिंग,वर्चुअल हियरिंग और ऑटोमेटेड नोटिस सिस्टम को केवल औपचारिकता न बनाकर वास्तविक रूप से लागू करना होगा।

छोटे दीवानी मामलों, ट्रैफिक उल्लंघन,उपभोक्ता विवाद, चेक बाउंस जैसे मामलों में प्राइवेट सेक्टर और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का सहयोग लेकर त्वरित निपटारा किया जा सकता है,जहां प्रशिक्षित मध्यस्थ, लोक अदालतें और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म हाथों-हाथ जुर्माना या समझौते के जरिए मामलों को समाप्त कर सकें। इससे अदालतों पर बोझ कम होगा और आम नागरिक को वर्षों तक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह भी जरूरी है कि न्याय केवल तेज ही नहीं,बल्कि न्यायपूर्ण और तर्कसंगत हो,क्योंकि जल्दबाजी में दिया गया अन्याय भी उतना ही खतरनाक है जितनी देरी।

इसके लिए विशेष बेंचों का गठन,विषय-विशेषज्ञ न्यायाधीशों की तैनाती और निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक है। सरकार को यह समझना होगा कि न्याय व्यवस्था पर खर्च कोई बोझ नहीं,बल्कि लोकतंत्र में निवेश है,क्योंकि जब जनता का न्यायपालिका पर भरोसा कमजोर होता है,तो व्यवस्था की नींव हिलने लगती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा 85 न्यायाधीशों की अनुशंसा एक ऐतिहासिक अवसर है, जिसे यदि समय रहते अमल में नहीं लाया गया,तो सुधार की यह किरण भी बुझ सकती है। अंततः शीघ्र न्याय तभी संभव है,जब पर्याप्त न्यायिक शक्ति,आधुनिक तकनीक,वैकल्पिक समाधान और राजनीतिक इच्छाशक्ति एक साथ आगे बढ़ें,अन्यथा न्याय में देरी,न्याय से इनकार की कहावत आने वाले दशकों तक हमारी न्याय प्रणाली का कड़वा सचाई बनी रहेगी!

# सवालों के घेरे में लिव इन संबंध

**वैवाहिक संस्था का विकल्प नहीं हो सकता...**

**लिव इन समर्थकों को सोशल साइंस रिसर्च में प्रकाशित शोध 'कोहैबिटेशन डिसोल्यूशन एंड साइकोलाजिकल डिस्ट्रेस अमंग यंग अडल्ट्स' को पढ़ना चाहिए। इस शोध के अनुसार लिव-इन संबंध टूटने के बाद अवसाद, मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ती है। लिव-इन संबंध का टूटना एक गंभीर तनावपूर्ण जीवन-घटना है,जिसके दूरगामी और घातक मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं...**

ऋतु सारस्वत

हाल में मद्रास हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के चलन पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे रिश्तों में महिलाओं को पत्नी का दर्जा देकर सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा, 'लिव-इन रिलेशन भारतीय समाज के लिए एक सांस्कृतिक झटका है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। लड़कियां सोचती हैं कि वे मार्डर्न हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करती हैं,लेकिन कुछ समय बाद उन्हें आभास होता है कि यह रिश्ता शादी की तरह कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है।'

तमाम अदालतें निरंतर इसके लिए चेता रही हैं कि लिव इन रिलेशनशिप अपेक्षाकृत लड़कियों के लिए सामाजिक स्तर पर कहीं अधिक नुकसानदायक है,लेकिन शायद युवाओं के लिए आधुनिक होने का तात्पर्य पश्चिमी संस्कृति को अपनाना हो गया है। उनका यह सोच उन्हें ऐसी स्थितियों में धकेल देता है, जहां से निकलने का हर प्रयास नाकाम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला कोई भी युगल न्यायालय के दरवाजे



खटखटाता हुआ नहीं दिखाई देता। अगस्त 2023 में 'अदनान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य' मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि अधिकांश लिव-इन जोड़ों के बीच ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद महिला के लिए समाज का सामना करना मुश्किल हो जाता है। एक तरह के सामाजिक बहिष्कार से लेकर अभद्र सार्वजनिक टिप्पणियां लिव-इन रिलेशनशिप के बाद उसके कष्टों का हिस्सा बन जाती हैं। जिस पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण कर युवा पीढ़ी लिव इन रिलेशनशिप अपना रही है, उसे यह जानना होगा कि आज भी पुरुषों और स्त्रियों के लिए स्पष्ट रूप से अलग नैतिक नियम हैं और इसका उदाहरण ब्रिएना पेरेली-हैरिस का शोध है, जो यूरोप के 11 देशों पर आधारित है। इसमें पाया गया कि लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक नकारात्मक दृष्टि, चरित्रगत संदेह और सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। शोध यह भी बताता है कि जहां पारंपरिक पारिवारिक और नैतिक मूल्य अधिक मजबूत हैं, वहां लिव-इन के बाद महिलाओं के लिए नए संबंधों में स्थापित होना, सामाजिक स्वीकृति पाना और सम्मानजनक जीवन में पुनः प्रवेश करना कहीं अधिक कठिन हो जाता है।

इसी असमान और कठोर सामाजिक व्यवहार को शोधकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से 'जेंडर्ड स्टिग्मा' कहा है। उक्त शोध यह स्थापित करता है कि लिव-इन संबंध महिलाओं के लिए केवल व्यक्तिगत विकल्प नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा सामाजिक जोखिम बन जाता है,जिसके दीर्घकालिक मानसिक,सामाजिक और भविष्यगत दुष्परिणाम होते हैं।

तमाम अध्ययन इस तथ्य को स्थापित कर रहे हैं कि 'लिव इन रिलेशनशिप' कभी भी वैवाहिक संस्था का विकल्प नहीं हो सकता। मनोविज्ञानी स्काट एम स्टैनली अपने 'स्लाइडिंग बनाम डिसाइडिंग सिद्धांत' में स्पष्ट करते हैं कि लिव-इन संबंधों में युवा अक्सर सोच-समझकर निर्णय नहीं लेते,बल्कि परिस्थितियों के साथ धीरे-धीरे फिसलते हुए बड़े जीवन-निर्णयों में प्रवेश कर जाते हैं। इन रिश्तों में स्पष्ट और सचेत प्रतिबद्धता नहीं होती। यही असंतुलन आगे चलकर भावनात्मक असुरक्षा, मानसिक तनाव और संबंधों की अस्थिरता का कारण बनता है। स्टैनली का शोध कहता है कि लिव-इन संबंध टूटने पर अवसाद, आत्मसम्मान में गिरावट और भविष्य के रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। स्टैनली का मानना है कि लिव-इन संबंध आकर्षक लग सकते हैं,पर वास्तव में वे उच्च-जोखिम वाले हैं, जिनके प्रायः नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। अदनान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी एक तरह से स्टैनली की विचारधारा को सत्यापित करते हुए दिखाई देती है कि विवाह संस्था व्यक्ति को जो सुरक्षा,सामाजिक स्वीकृति,प्रगति और स्थिरता प्रदान करती है, वह लिव-इन-रिलेशनशिप कभी नहीं दे सकता।

भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती उस संस्कृति के पीछे भागना है, जिसे पश्चिमी संस्कृति और बालीवुड ने स्थापित किया है। इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस देश में विवाह संस्था को नष्ट करने और समाज को अस्थिर करने और हमारे देश की प्रगति में बाधा डालने की व्यवस्थित योजना है। फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के प्रसारण से विवाह संस्था का खात्मा हो रहा है। विवाहित रिश्तों में साथी के साथ बेवफाई और स्वतंत्र लिव-इन-रिलेशनशिप को प्रगतिशील समाज की निशानी बताया जा रहा है।

युवा पीढ़ी ऐसे दर्शन की ओर आकर्षित हो रही है,क्योंकि उन्हें इसके दीर्घकालिक परिणामों का पता नहीं है। एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में कूदना किसी भी तरह से संतोषजनक जीवन नहीं है। विवाह संस्था व्यक्ति के जीवन को जो सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है, वह लिव-इन-रिलेशनशिप में अपेक्षित नहीं है। लिव इन समर्थकों को सोशल साइंस रिसर्च में प्रकाशित शोध 'कोहैबिटेशन डिसोल्यूशन एंड साइकोलाजिकल डिस्ट्रेस अमंग यंग अडल्ट्स' को पढ़ना चाहिए। इस शोध के अनुसार लिव-इन संबंध टूटने के बाद अवसाद, मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ती है। लिव-इन संबंध का टूटना एक गंभीर तनावपूर्ण जीवन-घटना है, जिसके दूरगामी और घातक मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं।

## प्यार...प्यार... और प्यार...



मुस्कान केशरी
मुजफ्फरपुर,बिहार

प्यार का कोई सही अर्थ बता सकता है क्या? मुझे लगता है कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है जो दो तन के बीच नहीं बल्कि दो मन के बीच होता है,जहां अटूट विश्वास, अपनेपन का एहसास होता है। दुनिया के नजरों से बचाकर रखना पड़ता है,बिन कहे एक-दूसरे की बातों को समझना पड़ता है। प्यार को बस प्यार कहने से नहीं बल्कि प्यार को निभाना पड़ता है। शायद यही बात लोग अब समझते नहीं है। इसलिए मन से पहले तन को चुनते हैं और वो भूल जाते है कि जिस रूप को देखकर उसने प्यार किया वो रूप भी एक दिन ढ़ल जाएगा। अंत में व्यवहार ही काम आएगा। प्यार की कोई परिभाषा होती नहीं है, प्यार एक एहसास है। प्यार में लोभ नहीं बल्कि निःस्वार्थ भाव हैं। प्यार में लुटना या लुटाना नहीं होता है, प्यार में साथ मिलकर आगे बढ़ना होता है। प्यार से ही दो दिल मिलते हैं, दिल मिलने से ही परिवार बढ़ते हैं। प्यार में जुदाई भी होती हैं लेकिन प्यार में धोखा नहीं होता और जो कर देते हैं प्यार में धोखा समझ जाइए कि वो प्यार नहीं करते हैं।

**सूचना**

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

# महात्मा गांधी का संदेश आज भी पूरे देश और दुनिया के लिए है प्रासंगिक : कन्हैया कुमार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रेहाना फाउंडेशन की ओर से शहर में मौन रैली और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत शाम करीब 4.30 बजे महामाया चौक से गांधी चौक तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा के समापन पर गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इस अवसर पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके पश्चात राजमोहिनी देवी भवन में आयोजित विचार गोष्ठी में उन्होंने अपने विचार रखे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी का संदेश आज भी पूरे देश और दुनिया के लिए प्रासंगिक है। बापू ने सत्य और अहिंसा का जो मार्ग दिखाया, वह केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मंत्र और संकल्प है। उन्होंने कहा कि गांधी के बलिदान दिवस पर अंबिकापुर की धरती से उसी संकल्प को दोहराया जाएगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में लोकतंत्र, जनतंत्र

के रूप में बना रहे और हिंसा तथा गोडसेवादी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव को रोका जाना चाहिए। यही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि गांधी का विचार किसी एक दल या विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरी मानवता की धरोहर है। विचार गोष्ठी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक,आदित्येश्वर सिंह देव,शफी अहमद सहित कांग्रेस के अन्य नेता,सेवा दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने महात्मा गांधी के जीवन, उनके संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया।

### अभाविप ने जताया विरोध

**इधर, कन्हैया कुमार के अंबिकापुर आगमन को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। अभाविप कार्यकर्ताओं का कहना था कि कन्हैया कुमार देशविरोधी व्यक्ति हैं और उन्होंने जेएनयू में देशविरोधी नारे लगाए थे,इसलिए वे युवाओं के आदर्श नहीं हो सकते। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में ऐसे व्यक्ति का स्वागत नहीं किया जाएगा। अभाविप ने स्वयं को स्वामी विवेकानंद के विचारों का अनुयायी बताते हुए कहा कि देशविरोधी सोच रखने वालों को अंबिकापुर के वासी स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि,विरोध के बावजूद मौके पर किसी तरह का प्रत्यक्ष प्रदर्शन या अप्रिय स्थिति देखने को नहीं मिली और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।**

# वैध मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश,कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म-7 का कथित दुरुपयोग कर कांग्रेस के परंपरागत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश का आरोप लगाते हुए कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है और चेतावनी दी है कि वैध मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सुनियोजित तरीके से वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने मांग की कि ऐसे मामलों में शामिल लोगों पर तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अम्बिकापुर विधानसभा क्षेत्र के उदयपुर तहसील अंतर्गत ग्राम डांड़गांव, में एक विशेष समूह के करीब 70 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म-7 में गलत जानकारी दी गई। आरोप है कि जीवित लोगों को मृत बताया गया और गांव में निवासरत लोगों को बाहर गया दर्शाकर नाम हटाने की सिफारिश की गई। इससे पहले उदारी, बकना, राजा कटेल से भी ऐसी ही बात सामने आई है। कांग्रेस ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि ऐसे कृत्य के लिए कानून में सजा का प्रावधान है। कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखे जाएं तथा झूठी शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाए। कलेक्टर ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनय शर्मा बंटी, लीगल सेल अध्यक्ष हेमंत तिवारी और यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकल झा शामिल थे।

# अंबिकापुर में हुई बैठक,आईडी तिवारी सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मनोनीत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर स्थित सांईबाबा मंदिर प्रांगण में प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत सरगुजा संभागीय सर्व ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, बैठक में सरगुजा संभाग के सभी जिलों से बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, बैठक का शुभारंभ सुंदरकांड पाठ से किया गया, तत्पश्चात फरस्सा पूजन संपन्न कराया गया,इसके पश्चात संभागीय अध्यक्ष के मनोनयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें सर्वसम्मति से आईडी तिवारी को सरगुजा संभागीय सर्व ब्राह्मण समाज का

अध्यक्ष मनोनीत किया गया, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में संभागीय कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा, प्रस्तावित संरचना के अंतर्गत संभागीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे तथा प्रत्येक जिले से एक-एक सह-सचिव का चयन किया जाएगा। समाज को संगठित करने का लिया संकल्प- अध्यक्षीय संबोधन में नवनियुक्त अध्यक्ष आईडी तिवारी ने कहा कि वे सरगुजा संभाग के सभी जिलों का दौरा कर ब्राह्मण समाज को संगठित करने का कार्य करेंगे,उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर सामाजिक समरसता,एकता और अनुशासन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समाज को एक मजबूत,अनुशासित और आदर्श संगठन के रूप में विकसित किया जाएगा,जो सामाजिक उत्थान और सकारात्मक दिशा में कार्य करेगा।

# राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि शहीद दिवस पर 30 जनवरी को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में 2 मिनट मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके पूर्व प्रातः 8 बजे कांग्रेस सेवादल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन से प्रभात फेरी निकालकर गांधी चौक स्थित बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक सेवादल के प्रदेश महासचिव एवं सरगुजा प्रभारी विनीत विशाल जायसवाल एवं सेवादल के जिला अध्यक्ष लोकेश कुमार की मौजूदगी में पार्टी और सेवादल कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी जी के प्रतिमा स्थल की साफ सफाई भी की ।

प्रभात फेरी के दौरान गांधी जी के प्रेरणादायक भजन जैसे 'रघुपति राघव राजा राम' और 'वंदे मातरम' गाते हुए सभी ने बापू के संदेशों को दोहराया। इस दौरान कांग्रेस

सेवादल महिला जिलाध्यक्ष प्रीति सिंह, आकाश,आशीष,जवाहर सोनी,विनोद इक्का, शिवम,बाल्केश्वर तिर्की,वीरेंद्र पाठक, विनोद सिंह, बीजू,नवनीत तिवारी,देविका सिंह, भारत सिंह,मो मुनव्वर,विशाल,लुकास एक्का,इरफान अंसारी,दीपक कुमार,अल्वीन विश्वकर्मा, अतुल कुमार, तुलेश्वर यादव के साथ ही साथ हेमंत सिन्हा, ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह धंजल,जगन्नाथ कुशवाहा,ए पी शांडिल्य,संजय सिंह, दुर्गेश गुप्ता,अनूप मेहता, जमील खान,नरेंद्र विश्वकर्मा,रजनीश सिंह, सोहन जायसवाल,शांतनु मुखर्जी,अविनाश कुमार,परवेज आलम गांधी,अमित वर्मा आदि उपस्थित थे।

**शराब दुकान नहीं की गई बंद, निंदनीय :** परंपरागत रूप से गांधी के शहादत दिवस 30 जनवरी को शराब दुकानों को बंद रखा जाता है। 2025 में भी इस दिन शराब दुकानों को बंद रखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समाज तक गांधी के सदाचार और नैतिक जीवन के संदेश को पहुंचाने का था। यह पहली बार है कि राज्य की भाजपा सरकार ने आज 30 जनवरी को ड्राई डे घोषित नहीं किया।

आबकारी विभाग के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को ही ड्राई डे के दिनों की घोषणा हो जाती है किंतु इस वर्ष के कैलेंडर में प्रारंभ से ही 30 जनवरी ड्राई डे के रूप में शामिल नहीं था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने प्रदेश सरकार की निंदा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की हत्या को गांधी वध मानने वाला संघ परिवार क्रमिक चरणों मे महात्मा गांधी को देशवासियों के बीच खारिज करने का प्रयास कर रहा है लेकिन यह संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही संघ परिवार मन वचनों से गोड़ासेवादी है लेकिन वैश्विक पटेल पर उसकी भी पहचान गांधी के देश के निवासी के रूप में है।

# नाबालिग लड़की की आत्महत्या के मामले में युवक गरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

नाबालिग लड़की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। प्रेमी शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था और बाद में शादी करने से इंकार कर दिया था। इस घटना से क्षुब्द व प्रताड़ित होकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व बतौली थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग लड़की की लाश फांसी पर लटकी हुई आम पेड़ पर मिली थी। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना कर रही थी। विवेचना के दौरान पाया गया कि उमेश यादव नामक युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर व शादी करने का झांसा देकर लड़की से बलात्कार किया था। बाद में वह शादी करने से इंकार कर दिया था। इस घटना से क्षुब्द होकर व प्रताड़ित होकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने आरोपी उमेश कुमार यादव पिता राजाराम उम्र 24 वर्ष निवासी मुर्ताडांड चिपरकाया थाना बतौली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 65(1), 64(2)(एम), 107 बीएनएस, 4, 6 पोक्सो एक्ट एवं 3 (2) (1) एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

# अंबिकापुर-रायगढ़ मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर-रायगढ़ मार्ग पर स्थित लुचकी घाट के पास बेकाबू अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक में तीन युवक सवार थे। जिसमें दो युवक वाहन के पहिए में फंस गए और दोनों को घसिटते हुए लगभग 100 मीटर दूर तक ले गया। दोनों युवकों का शव पूरी तरह पीस गया। चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया है। सूचना पर कोतवाली व ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को मरच्यूरी भिजवाया। वहीं गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार तीन व्यक्ति अंबिकापुर से सीतापुर की ओर जा रहे थे। शाम करीब 6.30 बजे अंबिकापुर-रायगढ़ मार्ग स्थित चुलकी घाट के ऊपर पहुंचे ही थे कि अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में दो युवक वाहन के पहिए में फंस गए,जिसे घसिटते हुए लगभग 100 मिटर तक ले गया। वाहन में फंसे रहने व सडक़ पर घसिटाने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और शव पूरी तरह पिस गया। वहीं तीसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। मृतक की पहचान सीतापुर निवासी आदित्य खाखा व अनिल तिर्की के रूप में हुई है। सूचना पर कोतवाली व ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के मोबाइल से परिजन से बात की तो पता चला कि तीनों सीतापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीनों अंबिकापुर से वापस घर लौट रहे थे। पुलिस ने दोनों के शव को पीएम के लिए मरच्यूरी में रखवा दिया है।

# धान खरीदी का समय 15 फरवरी तक बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया चक्काजाम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

धान खरीदी की समय-सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लखनपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे-43 पर सांकेतिक चक्काजाम कर धरना-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सडक़ पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की,जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा।

धरना को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादों के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत किसान का धान खरीदने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है,जबकि अब भी बड़ी संख्या में किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं। कांग्रेस

कार्यकर्ताओं ने मांग की कि धान खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी की जाए तथा पंजीकृत किसानों का दाना-दाना धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। नेताओं का कहना था कि खरीदी के लिए कम समय मिलने के कारण किसान मजबूरी में अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को औने-पौने दामों पर बेचने को विवश हो रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा।

# यूरोकिड्स प्री-स्कूल,अंबिकापुर को छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नामांकन का पुरस्कार...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

यूरोकिड्स प्री-स्कूल, अंबिकापुर को छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक नामांकन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह 20 जनवरी 2026 को होटल फेयरमोंट, मुंबई में आयोजित किया गया। यह पुरस्कार यूरोकिड्स के सीईओ द्वारा प्रदान किया गया, जिसे यूरोकिड्स प्री-

स्कूल, अंबिकापुर की प्रबंधन टीम के सदस्य श्री नितीश दीक्षित ने विद्यालय की ओर से प्राप्त किया। यह सम्मान विद्यालय के उत्कृष्ट प्रदर्शन, निरंतर प्रगति तथा अभिभावकों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। इस उपलब्धि के पीछे स्कूल प्रबंधन,शिक्षकों, स्टाफ और अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यूरोकिड्स प्री-स्कूल,अंबिकापुर का प्रबंधन इस गौरवपूर्ण सम्मान के लिए यूरोकिड्स नेतृत्व का आभार व्यक्त करता है और भविष्य में भी बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के अपने संकल्प को दोहराता है।

# सरगुजा में एंटी-रेबीज इंजेक्शन की भारी कमी,नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए : कैलाश मिश्रा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के बीच एंटी-रेबीज इंजेक्शन की कमी गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। जिले में प्रतिदिन औसतन 10 से 15 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। विगत वर्ष लगभग 4649 लोगों को कुत्तों ने काटा,लेकिन इसके बावजूद जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी-रेबीज टीकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है।एंटी-रेबीज इंजेक्शन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने को तैयार सामाजिक कार्यकर्ता व भाजपा एन जी ओ प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक कैलाश मिश्रा ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। श्री मिश्रा द्वारा बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी-रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को बाजार से महंगे दामों पर टीके खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। गंभीर मामलों में आवश्यक इम्युनोग्लोबुलिन (आईआरजी) की सुविधा भी अधिकांश केन्द्रों में उपलब्ध नहीं है। शहरी स्वास्थ्य केन्द्र नवापारा में भी लंबे समय से एंटी-रेबीज इंजेक्शन की कमी बनी हुई है। इस बीच एक ताजा मामले में तीन एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगने के बावजूद एक व्यक्ति की मौत हो जाने से टीकों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना के बाद आमजन में भय और असंतोष का माहौल है। इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि सरगुजा जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गुणवत्तापरक एंटी-रेबीज इंजेक्शन तथा इम्युनोग्लोबुलिन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि कुत्तों के काटने से पीड़ित मरीजों को समय पर समुचित इलाज मिल सके।

# तेज रफ्तार पिकअप उछलकर चलती कार पर गिरी,मचा हड़कंप

-संवाददाता-
सूरजपुर 30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिले में शुक्रवार को एक बेहद अजीबो-गरीब और चौंकाने वाली सड़क दुर्घटना सामने आई है, जिसने राहगीरों और स्थानीय लोगों को दहला कर रख दिया। इस सनसनीखेज हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह तेज रफ्तार में आ रही एक मालवाहक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर उछलती हुई चलती कार के ऊपर जा गिरती है। यह पूरी घटना कुछ ही सेकेंड में घटी, लेकिन इसके परिणाम बेहद गंभीर रहे। जानकारी के अनुसार यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (एनएच-43) पर बिश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एस्सार पेट्रोल पंप के पास हुआ। स्विफ्ट डिजायर कार सूरजपुर से बिश्रामपुर की ओर जा रही थी। जैसे ही कार पेट्रोल पंप की ओर

मुड़ी, उसी समय अंबिकापुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही मालवाहक Also Read - कुरुषनार में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बनेगा अतिरिक्त कक्ष पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित हो गई। पिकअप वाहन सड़क पर उछलते हुए सीधे सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार के ऊपर पलट गई। सीसीटीवी फुटेज में हादसे का भयावह दृश्य स्पष्ट रूप से नजर आता है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पिकअप वाहन हवा में उछलकर कार के ऊपर चढ़ जाती है और कुछ पल तक कार के ऊपर ही पलटी रहती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसका चालक केबिन के अंदर ही फंस गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। कार चालक वाहन के अंदर बुरी तरह फंसे हुए थे,जिन्हें बाहर निकालना आसान नहीं था। बाद में कटर मशीन की मदद से कार को काटकर चालक को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल कार चालक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया,जहां उनका इलाज जारी है। इस भीषण हादसे में गनीमत यह रही कि पिकअप वाहन का चालक टक्कर के वक्त ही वाहन से बाहर निकल गया,जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि हादसे के कारण कुछ समय के लिए एनएच-43 पर यातायात भी बाधित हो गया।

# विदाई समारोह के नाम पर यातायात नियमों की अवहेलना पर सख्ती

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

विगत वर्षों की भाँति वर्तमान वर्ष में भी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो संज्ञान में आए हैं,जिनमें कुछ विद्यालयीन छात्र-छात्राएं विदाई समारोह के पश्चात विद्यालय से बाहर पृथक पार्टी का आयोजन करते हुए तथा उत्तेजक एवं अनियंत्रित रूप से दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह कृत्य यातायात नियमों के प्रति घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जिससे न केवल विद्यार्थियों बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा द्वारा जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि सभी विद्यालयों में विदाई समारोह का आयोजन पूर्णतः मर्यादित, अनुशासित एवं विद्यालय परिसर के भीतर ही किया जाए। विदाई समारोह में विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व एवं अनुशासन की भावना विकसित हो सके। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में विदाई समारोह विद्यालय परिसर के बाहर-जैसे होटल,पार्क,रेस्टोरेंट अथवा अन्य किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर-आयोजित नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों को यातायात नियमों के उल्लंघन, तेज गति, स्टंट अथवा असुरक्षित वाहन संचालन से दूर रहने हेतु सख्त हिदायत देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

CMYK

# जनप्रतिनिधि नहीं जानेंगे जमीनी सच्चाई,तो मितानिन बताएंगी-आंदोलन के मंच से गूंजी दो टूक चेतावनी

## गांव-गांव की पीड़ा लेकर सड़कों पर उतरीं मितानिनें,मंच से प्रशासन को चेतावनी...

- एक नहीं अनेक हैं समस्याएंः मितानिनों के आंदोलन ने खोल दी सिस्टम की परतें...
- सोनहत में मितानिनों का जनआंदोलन, सरकार और जनप्रतिनिधियों को दिखाया जमीनी आईना...
- जो जनप्रतिनिधि नहीं देख पाए, वह मितानिनों ने मंच से दिखा दिया...
- साल भर चुप्पी,एक दिन विस्फोटः मितानिन आंदोलन में फूटा जनाक्रोश

**सरकार की आंखें बंद, मितानिनों की आंखों में गांव का सच**

**नारे नहीं,आंकड़े लेकर उतरीं मितानिनें-सिस्टम की नींद टूटी**

**सोनहत में मितानिनों का हल्लाबोल स्वास्थ्य,सड़क, पानी,बिजली और राशन संकट को लेकर विशाल रैली,सम्मेलन में बंद सोनोग्राफी सेवा चालू करने बुलंद हुई आवाज**

-राजन पाण्डेय-

**सोनहत (कोरिया),30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।**

सम्मेलन के मंच से मितानिन बहनों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि जनप्रतिनिधियों को अपने ही क्षेत्र की समस्याएं नहीं पता हैं, तो यह उनकी सबसे बड़ी विफलता है,और अगर वे जमीनी हकीकत से अनजान बने रहेंगे,तो मितानिनें उन्हें आईना दिखाने का काम करेंगी, मितानिन बहनों ने कहा कि जब वे अपने-अपने गांवों से पूरे साल समस्याएं इकट्ठा कर आंदोलन के मंच पर लेकर पहुंचीं,तब यह स्पष्ट हो गया कि सोनहत क्षेत्र किसी एक समस्या से नहीं,बल्कि दर्जनों जमीनी संकटों से जूझ रहा है,स्वास्थ्य,सड़क, पानी,बिजली,राशन,नेटवर्क–ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा,जहां अव्यवस्था न हो,मितानिनों ने दो टूक कहा कि वे केवल सरकार की एक मानदेय इकाई भर नहीं हैं,बल्कि गांव-गांव की नब्ज पहचानने वाली जमीनी ताकत हैं, वे हर गांव में मौजूद हैं,हर परिवार से जुड़ी हैं और इसलिए उन्हें पता है कि किस घर में पानी नहीं है,किस महिला को इलाज नहीं मिला और किस गांव में आज भी अंधेरा पसरा है,मितानिन बहनों ने मंच से यह भी कहा कि वे पूरे वर्ष अपने काम के साथ-साथ गांव-गांव जाकर समस्याओं का दस्तावेज तैयार करती हैं। यह कोई औपचारिकता नहीं,बल्कि एक संघर्ष है–जो साल भर चलता है और साल में एक दिन आंदोलन बनकर फूट पड़ता है, उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यह आंदोलन सिर्फ मांगपत्र सौंपने तक सीमित नहीं है,यदि शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अब भी आंखें मूंदे रखीं, तो आने वाले समय में यह आवाज और तेज होगी,सड़कों से लेकर सदन तक गूंजेगी, मितानिनों ने कहा कि वे आंकड़ों की भाषा नहीं, जमीनी सच्चाई बोलती हैं–और यही सच्चाई आज प्रशासन को सबसे ज्यादा चुभ रही है।

### महिला डॉक्टर की अनुपस्थिति बनी बड़ी समस्या...

सम्मेलन में यह भी बताया गया कि सोनहत अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर का पद वर्षों से रिक्त है,ऐसे में प्रसव,स्त्री रोग एवं जटिल मामलों में महिलाओं को बैकुंठपुर या अंबिकापुर रेफर किया जाता है,मितानिनों का कहना था कि'जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही महिला डॉक्टर नहीं होगी तो ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित इलाज कैसे मिलेगा? '

### नसबंदी और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर नहीं लगे...

लंबे समय से क्षेत्र में महिला नसबंदी, मोतियाबिंद ऑपरेशन के शिविर आयोजित नहीं किए गए हैं,इससे सैकड़ों मरीज प्रतीक्षा सूची में हैं। मितानिनों ने नियमित विशेष शिविर लगाने की मांग की।

### जननी सुरक्षा योजना की राशि अब तक लंबित

सम्मेलन में कई मितानिनों ने बताया कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि कई हितग्राहियों को आज तक नहीं मिली है, इससे गरीब परिवारों में नाराजगी बढ़ रही है।

### सोनहत अस्पताल की बदहाल व्यवस्था बनी आंदोलन का केंद्र...

सम्मेलन में मितानिनों ने सोनहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली पर खुलकर नाराजगी जाहिर की,वक्ताओं ने कहा कि अस्पताल में सुविधाओं का घोर अभाव है,जिसका सीधा असर गरीब ग्रामीणों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा है,सोनोग्राफी मशीन वर्षों से बंद सबसे गंभीर मुद्दा सोनहत अस्पताल में लंबे समय से बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन को लेकर रहा, मितानिनों ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच नहीं हो पा रही,मजबूरी में निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा,कई महिलाएं आर्थिक तंगी के कारण जांच ही नहीं करा पातीं मितानिनों ने मांग की कि सोनोग्राफी सेवा प्रतिदिन नियमित रूप से चालू की जाए।

### मोबाइल नेटवर्क आज भी सपना

रामगढ़ सहित कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है।न नेटवर्क है,न इंटरनेट, इससेऑनलाइन सेवाएं बाधित,आपातकालीन कॉल संभव नहीं,छात्रों की पढ़ाई प्रभावित, ग्रामीणों ने इसे डिजिटल इंडिया के दावों पर सवाल बताया।

### नल-जल योजना की जमीनी सच्चाई आई सामने...

सरकारी दावों के विपरीत सोनहत क्षेत्र में नल-जल योजना धरातल पर विफल नजर आई, पाइपलाइन तो बिछा दी गई,नल लगाए गए लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा,कई गांवों में टोटियां टूटी हुई हैं,कहीं मोटर खराब है,तो कहीं टंकी अधूरी बनी हुई है,ग्रामीण आज भी हैंडपंप और नदी-नालों पर निर्भर हैं।

### वनांचलों में अंधेराः सौर ऊर्जा प्लांट बने शोपीस...

सोनहत के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में लगाए गए सौर ऊर्जा प्लांट और सोलर लाइटें वर्षों से बंद पड़ी हैं,बैटरियां खराब,पैनल टूटे,मेंटेनेंस पूरी तरह ठप्प,रात होते ही गांव अंधेरे में डूब जाते हैं,जिससे सुरक्षा और आवागमन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

### अमृतपुर से सूक्तरा सड़क नहीं,तो विकास नहीं...

सम्मेलन में वनांचल की सबसे बड़ी समस्या अमृतपुर-सूक्तरा सड़क को बताया गया, सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती,बरसात में गांव पूरी तरह कट जाते हैं, स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंच कठिन हो जाती है, मितानिनों ने इसे क्षेत्र की जीवनरेखा बताते हुए तत्काल पक्की सड़क निर्माण की मांग की।

### पोड़ी ओदारी में राशन संकट...

सम्मेलन में यह भी सामने आया कि पोड़ी ओदारी क्षेत्र में महीनों से शक्कर,चना का वितरण नहीं हुआ है,गरीब परिवारों को अधूरा राशन मिल रहा है। मितानिनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

**पूर्व विधायक गुलाब कमरो का सरकार को अल्टीमेटम :** मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा 'मितानिनें केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं, बल्कि ग्रामीण व्यवस्था की नींव हैं।

यदि उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो यह आंदोलन और व्यापक होगा।' उन्होंने ऐलान किया कि सोनोग्राफी और महिला डॉक्टर का मुद्दा स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाया जाएगा, मितानिन मानदेय व सुविधाओं को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के माध्यम से उठाया जाएगा।

### जनप्रतिनिधियों ने जताया समर्थन

**आशा देवी सोनपाकर (अध्यक्ष, जनपद पंचायत) :** 'जब तक स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं होंगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। '

**पुष्पेंद्र राजवाड़े :** 'अमृतपुर-सूक्तरा सड़क पूरे क्षेत्र की प्राथमिक जरूरत है। '

**अविनाश पाठक (सांसद प्रतिनिधि) :** 'नल-जल और नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाएं जनता का अधिकार हैं। '

**संदीप जायसवाल (अध्यक्ष) :** 'मोबाइल नेटवर्क के लिए प्रयास जारी हैं, मितानिन भवन शीघ्र सौंपा जाएगा। '

### मितानिनों की 13 सूत्रीय प्रमुख मांगें

1. सोनहत अस्पताल में सोनोग्राफी सेवा चालू हो
2. महिला डॉक्टर की स्थायी नियुक्ति
3. नसबंदी एवं मोतियाबिंद शिविर
4. जननी सुरक्षा राशि का भुगतान
5. पोड़ी क्षेत्र में शक्कर-चना वितरण
6. दूरस्थ क्षेत्रों में नई राशन दुकान
7. अमृतपुर-सूक्तरा सड़क निर्माण
8. सौर ऊर्जा प्लांट मरम्मत
9. खराब सोलर लाइट दुरुस्त हों
10. नल-जल योजना की तकनीकी खामियां दूर हों
11. हर घर जल आपूर्ति सुनिश्चित हो
12. रामगढ़ क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क
13. अधूरी सीसी सड़कें पूर्ण हों

# विकासखण्ड स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 03 से 06 फरवरी तक होंगे आयोजित

## मुख्यमंत्री ने किया सरगुजा ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह (लोगो) एवं शुभंकर 'गजरु' का अनावरण

-संवाददाता-

**सूरजपुर,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।**

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप एवं छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर के निर्देशानुसार सरगुजा ओलंपिक वर्ष 2025-26 का आयोजन सूरजपुर जिले के समस्त विकासखण्डों में किया जाएगा, जिला कलेक्टर एस. जयवर्धन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में इस बहुप्रतीक्षित खेल महोत्सव की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, विकासखण्ड स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2025-26 का आयोजन 03 फरवरी से 06 फरवरी 2026 तक किया जाएगा, जिसमें जिलेभर के खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

### मुख्यमंत्री ने किया प्रतीक चिन्ह एवं शुभंकर 'गजरु' का अनावरण...

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले सरगुजा ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह (लोगो) एवं शुभंकर 'गजरु' का विधिवत अनावरण किया, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरगुजा अंचलवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब बस्तर की तरह सरगुजा की खेल प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का सशक्त मंच मिलेगा। यह आयोजन आदिवासी युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा।

### आदिवासी अंचल की खेल प्रतिभाओं को मिलेगा मंच

सरगुजा संभाग अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है,जहां खेलों के क्षेत्र में अपार नैसर्गिक प्रतिभा विद्यमान है। शासन द्वारा सरगुजा ओलंपिक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं वनांचल युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना, उनकी खेल एवं रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करना, भविष्य के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना है।

### 10 से अधिक खेल विधाओं में होंगी प्रतियोगिताएं

सूरजपुर जिले में आयोजित विकासखण्ड स्तरीय सरगुजा ओलंपिक में 10 से अधिक खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी।

### मुख्य खेल विधाएंः

- तीरंदाजी (इंडियन राउंड - 30 मीटर एवं 50 मीटर)
- कबड्डी
- बैडमिंटन
- फुटबॉल
- हॉकी
- कुश्ती
- खो-खो
- वॉलीबॉल
- बास्केटबॉल
- एथलेटिक्स

### एथलेटिक्स में होंगी ये स्पर्धाएं

एथलेटिक्स खेल विधा के अंतर्गत
100 मीटर दौड़
200 मीटर दौड़
400 मीटर दौड़
लंबी कूद
ऊंची कूद
शॉटपुट
डिस्कस थ्रो
जैवेलिन थ्रो
4×100 मीटर रिले दौड़
की प्रतियोगिताएं
आयोजित की जाएंगी।

### जनभागीदारी से नई ऊंचाइयों को छुएगा सरगुजा ओलंपिक...

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जिस प्रकार बस्तर ओलंपिक को जनभागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान मिली,उसी प्रकार सरगुजा ओलंपिक भी पूरे अंचल के सहयोग से नई ऊंचाइयों को छुएगा, उन्होंने पंजीयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया कि सरगुजा अंचल के युवा पूरे उत्साह,उमंग और जोश के साथ इस खेल महोत्सव के लिए तैयार हैं।

### खेल प्रतिभाओं के लिए मील का पत्थर बनेगा आयोजन...

सरगुजा ओलंपिक 2025-26 निश्चित रूप से आदिवासी अंचलों की छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने,ग्रामीण युवाओं को नई पहचान दिलाने, खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा।

### कराते प्रतियोगिता के आयु वर्ग

**कराते खेल में निम्न वर्गों में मुकाबले होंगेः-**

**जूनियर बालक वर्ग**
- 14-15 वर्ष : 42-47 किलोग्राम
- 16-17 वर्ष : 55 एवं 61 किलोग्राम

**जूनियर बालिका वर्ग**
- 14-15 वर्ष : 42-47 किलोग्राम
- 16-17 वर्ष : 53 किलोग्राम

**सीनियर वर्ग**
- पुरुष : 60-67 किलोग्राम
- महिला : 55-61 किलोग्राम
- महिला वर्ग के लिए रस्साकसी

**प्रदर्शनात्मक खेलः रस्साकसी खेल को केवल महिला वर्ग के लिए प्रदर्शनात्मक रूप में शामिल किया गया है, जिसमें...**
- जूनियर वर्ग
- सीनियर वर्ग

के लिए पृथक वेट ग्रुप निर्धारित किए गए हैं।

**कुश्ती और हॉकी सीधे जिला से संभाग स्तर पर : कुश्ती एवं हॉकी खेल विधाओं में–** दलों की भागीदारी सीधे जिला स्तर से संभाग स्तर पर होगी।

**इन खेलों में प्रतियोगिताएं...**
- 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग
- सीनियर वर्ग (कोई आयु सीमा नहीं) में आयोजित की जाएंगी।

# राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में 'असुरक्षा रैली'

# जब हेलमेट नहीं,हौसले पहने गए...

**सड़क सुरक्षा माह में बिना हेलमेट का नेतृत्वः नियम भाषणों के लिए,स्टंट सड़कों के लिए...**

**हेलमेट उतारो, झंडा लगाओः सड़क सुरक्षा माह में असुरक्षा की रैली**

**जब हेलमेट से ज़्यादा जरूरी हो गया शक्ति प्रदर्शन...सुरक्षा का संदेश या असुरक्षा का प्रदर्शन?**

**राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में नियमों की खुलेआम उड़ती धज्जियाँ**

## युवाओं को दिया गया संदेश या जोखिम का प्रशिक्षण?

भाजपा युवा मोर्चा स्वयं युवाओं का संगठन है,युवाओं से अपेक्षा रहती है कि वे समाज को दिशा देंगे,लेकिन इस रैली ने युवाओं को जो संदेश दिया,वह कुछ ऐसा रहा अगर राजनीतिक झंडा है,तो हेलमेट वैकल्पिक है,यह संदेश खतरनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी।

### व्यंग्य यह नहीं कि रैली निकली,व्यंग्य यह है कि सीख गलत मिली

सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य लोगों को डराना नहीं,बचाना है,लेकिन जब नेतृत्व ही यह संदेश दे देखो,हम नियम नहीं मानते,फिर भी चल रहे हैं,तो आम नागरिक यही सीखेगा कि,अगर ताकत है,तो नियम की ज़रूरत नहीं।

### हेलमेट सिर पर नहीं,सोच में चाहिए...

यह खबर किसी दल विशेष के विरोध में नहीं, बल्कि उस मानसिकता पर व्यंग्य है जहां नियम भाषणों में अच्छे लगते हैं,लेकिन पालन करते समय बोझ लगते हैं,क्योंकि सड़क पर नेता की बाइक भी उतनी ही फिसलती है,कार्यकर्ता की जान भी उतनी ही कीमती है,और दुर्घटना किसी का झंडा नहीं देखती।

### सुरक्षा माह नहीं,साहस प्रदर्शन माह समझ लिया गया...

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य था लोगों को दुर्घटना से बचाना, लेकिन कुछ लोगों ने शायद इसे समझ लिया राष्ट्रीय स्टंट प्रदर्शन माह। बाइकों पर युवा सवार हैं,कुछ आगे बैठे हैं,कुछ पीछे खड़े हैं,और कुछ शायद यह मान चुके हैं कि अगर राजनीतिक झंडा लगा है,तो हेलमेट वैकल्पिक है।

### हेलमेट से ज़्यादा जरूरी फोटो निकली

कहा जाता है, सिर की सुरक्षा ज़रूरी है,लेकिन रैली में दिखा कि सिर से ज्यादा सोशल मीडिया की प्रोफाइल सुरक्षित करनी थी,हेलमेट पहनते तो चेहरा नहीं दिखता,रील अच्छी नहीं बनती,शक्ति प्रदर्शन फीका लग जाता, तो फिर जोखिम ही क्यों न लिया जाए?

-संवाददाता-
कोरिया,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

जनवरी का महीना है हर चौराहे पर बैनर टंगे हैं 'हेलमेट पहनें,जीवन बचाएं।' पुलिस चालान काट रही है, स्कूलों में बच्चों को समझाया जा रहा है, सरकार कह रही है – 'दुर्घटना नहीं,सतर्कता चाहिए।' और ठीक उसी समयज्कोरिया जिले की सड़क पर एक रैली निकलती है जिसमें हेलमेट नहीं,हौसले पहने गए हैं, नंबर प्लेट नहीं,पहचान काफी है, और नियम नहीं,सिर्फ जोश है। यह लेख किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है,यह उस मानसिकता के खिलाफ है जहां नियम भाषणों में अच्छे लगते हैं,लेकिन पालन करते समय बोझ लगते हैं,जहां जनता को उपदेश दिए जाते हैं,और सड़क पर खुद अपवाद बन जाया जाता है। बताया गया कि यह रैली भाजपा के एक कार्यक्रम में पटना आगमन के अवसर पर निकाली गई, स्वागत हुआ,उत्साह था,जोश था – और फिर जोश में होश कहीं रास्ते में उतर गया, पूरी युवा टीम बाइक पर सवार हुई, कुछ बैठे थे, कुछ पीछे खड़े थे,कुछ हवा से बातें कर रहे थे, और कुछ शायद सोच रहे थे–हेलमेट पहनेंगे तो फोटो खराब आ जाएगी।

## जहां मिसाल बननी थी,वहां मज़ाक बन गया अभियान

अगर यही युवा मोर्चा हेलमेट पहनकर, नियमों का पालन कर,सड़क सुरक्षा अपनाएं का नारा लगाते हुए रैली निकालता,तो पूरा जिला कहता देखो, नेतृत्व ऐसे होता है,लेकिन अब जिला कह रहा है देखो, नियम ऐसे तोड़े जाते हैं।

## दुर्घटना किसी की पहचान नहीं देखती

सड़क पर नेता की बाइक भी फिसलती है, कार्यकर्ता की जान भी जाती है और एम्बुलेंस यह नहीं पूछती कि आप किस संगठन से हैं? दुर्घटना केवल एक बात देखती है लापरवाही।

## अंतिम कटाक्ष

सड़क सुरक्षा माह में अगर हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं था,तो कम से कम यह तो याद रखा जाता कि दुर्घटना कभी चुनाव चिन्ह नहीं देखती।

## आखिरी पंक्ति (कटाक्ष में)

सड़क सुरक्षा माह में हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं था,ज़रूरी था सिर्फ जोश दिखाना और जोश में जब होश उतर जाए,तो उसे ही शायद आजकल 'युवा नेतृत्व' कहा जाता है।

**जब सवाल खड़े हों, तो जवाब भी जरूरी हैं,अब सवाल ये नहीं हैं कि...रैली क्यों निकाली गई बल्कि सवाल ये हैं कि...**

बिना हेलमेट रैली कैसे निकली?
बिना नंबर प्लेट वाहन सड़क पर कैसे दौड़े?
क्या यातायात पुलिस को जानकारी थी?
क्या कोई चालानी कार्रवाई हुई?
या फिर यह भी 'विशेष परिस्थिति' थी?

## नियम सिर्फ आम आदमी के लिए होते हैं क्या?

यह सवाल अब चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रहा है, आम आदमी बिना हेलमेट पकड़ा जाए ?1000 जुर्माना, बिना नंबर प्लेट ? गाड़ी जब्त लेकिन राजनीतिक रैली में,नियम वैकल्पिक,चालान अदृश्य,कानून मौन शायद कानून की किताब में अब नया अध्याय जुड़ गया है यह नियम लागू नहीं होगा, यदि वाहन पर झंडा लगा हो।

## युवा नेतृत्व या जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण?

युवा मोर्चा युवाओं का संगठन है,युवाओं को दिशा देना इसका उद्देश्य है,लेकिन इस रैली ने युवाओं को यह दिशा दी जोश दिखाओ, होश मत ढोओ, यह नेतृत्व कम और जोखिम प्रबंधन में फेल होती ट्रेनिंग ज्यादा लगी। विडंबना देखिए – दो दिन बचे थे- 31 जनवरी को सड़क सुरक्षा माह खत्म होना था,सिर्फ दो दिन शेष थे,लेकिन उससे पहले यह दृश्य आ गया,मानो अभियान खुद कह रहा हो मुझसे मज़ाक ही करना था तो मुझे शुरू क्यों किया?

### कोरबा में पुल के बाद रेलवे पटरी भी चोरी, करोड़ों की रेल सामग्री गायब

-संवाददाता-
कोरबा,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कबाड़ चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले 30 टन लोहे के पुल की चोरी के बाद अब चोरों ने रेलवे लाइन को भी निशाना बनाया है। कुसमुंडा से कुचेना-जटगा के बीच नई बिछाई जा रही रेल लाइन से पटरी और अन्य लोहे की सामग्री काटकर ले जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 60 से 65 किलोमीटर के दायरे में करोड़ों रुपए का रेल सामग्री गायब पाई गई है। चोरी की घटनाएं अलग-अलग दिनों में हुई हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि गेवरा-पेंड्रा नई रेल लाइन परियोजना का कार्य चल रहा है, जिसे शिवाकृति प्राइवेट कंपनी द्वारा बिछाया जा रहा है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक करीब 2 करोड़ रुपए की रेल सामग्री चोरी हो चुकी है। इस संबंध में कंपनी प्रबंधन ने बांकीमोंगरा और कटघोरा थानों में शिकायत दर्ज कराई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि रेल लाइन निर्माण में चोरी की शिकायत मिली है और पुलिस टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 17 जनवरी को कोरबा में 40 साल पुराने लोहे के पुल की चोरी का बड़ा मामला सामने आया था। पुलिस ने पुल काटकर चुराने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। ढोढ़ीपारा इलाके में स्थित पुल से 80 फुट लंबी लोहे की रेलिंग को गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और एलपीजी सिलेंडर की मदद से रातभर में काटकर चुराया गया था। पुल और अब रेल पटरी चोरी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा।

# कोरबा में बीए छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या,मां की फटकार से थी आहत

-संवाददाता-
कोरबा,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान आरती टंडन के रूप में हुई है, जो जांजगीर-चांपा जिले के गुमिया गांव की रहने वाली थी और कोरबा में रहकर बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी।

जानकारी के अनुसार, आरती बुधवार को कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी,लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और सहेलियों व आसपास के लोगों से पूछताछ की,लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान परिजनों को बांकीमोंगरा के घुड़देवा स्थित पुराने क्वार्टर की चाबी गायब मिली। यह क्वार्टर आरती के नाना का है,जो एसईसीएल से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। आशंका के आधार पर परिजन वहां पहुंचे, जहां कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। आरती के भाई ने दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया,जहां पंखे से लटका हुआ उसका शव मिला।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि आरती अपनी मां की फटकार से नाराज थी। पिता अजीत टंडन ने बताया कि मां ने घर के काम को लेकर उसे समझाया था,जिससे वह आहत हो गई। उन्होंने कहा कि आरती पढ़ाई में अच्छी थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा कदम उठा लेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूछताछ जारी है।

## न्यायालय तहसीलदार लटोरी जिला सूरजपुर छ0ग0

**मामले की श्रेणी :राजस्व**

संदर्भ :- जिला- सूरजपुर तहसील-लटोरी प.ह.न. - 00019 हीराडबरी ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक-. CT202526640721600003

**ईश्तहार**

तहसील लटोरी के प.ह.न. 00019 के अंतर्गत ग्राम हीराडबरी के वर्तमान भूमिस्वामी फुलेश्वरी पिता/पति-समरथ पता-सा,देह. लालमनी पिता/पति-देवन पता-सा,देह, कलेश्वरी पिता/पति-समरथ पता-सा,देह, रूबी पिता/पति-देवन पता-सा,देह, लालसाय पिता/पति-समरथ पता-सा,देह, बसन्ती पिता/पति देवन पता-सा,देह, लालमोहन पिता/पति देवन पता-सा, देह, चंद्रवती पिता/पति-देवन पता-सा,देह, रामसाय पिता/पति-समरथ पता-सा देह, सुबरती पिता/पति - देवन पता-सा, देह के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 224 /2 (1.8600), 244/2(0.3400) में प्रस्तावित भूमिस्वामी/ क्रेता लालसाय पिता/पति - समरथ पता - महेशपुर, फुलेश्वरी पिता/पति - समरथ पता कसलगिरी के नाम पर पंजीयन / फ़ौती होने के उपरांत नामांतरण / अभिलेख दुरुस्ती / खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 16/02/2026 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय न्यायालय तहसीलदार लटोरी पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो इश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं / अधिवक्ता / आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते हैं। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 23/01/2026 को जारी किया जाता है।

surendra kumar painkra
सील
**तहसीलदार**
तहसील - लटोरी,जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

## न्यायालय तहसीलदार भटगांव जिला सूरजपुर छ0ग0

**ईश्तहार**

रा0प्र0क्र0 202601261300030 ब-121 / 2025-2026

विजय प्रकाश प्रति छ0ग0शासन आम जनता ग्राम भटगांव को सूचित किया जाता है कि आवेदक विजय प्रकाश आ0 स्व0 मुरीत राम उम्र 30 वर्ष जाति सतनामी, उर्मिला सोनवानी आ0 मुरीत राम जाति सतनामी तहसील भटगांव जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया है कि आवेदकगण के पिता मुरीत राम आ0 तिलक भटगांव क्षेत्र भूमिगत खदान भटगांव मे कार्यरत थे, जिनका सेवा पुस्तिका क्रमांक नम्बर जे.बी.पी./ 603072 मे आश्रितो का पुकारू नाम गुड्डू आ0 मुरीत राम तथा रूकमनी आ0 मुरीत राम नाम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजो वास्तविक नाम विजय प्रकाश आ0 मुरीत राम व उर्मिला सोनवानी आ0 मुरीत राम दर्ज है। नाम भिन्नता होने के कारण मुरीत राम जी.पी.एफ. पैसा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। आवेदक द्वारा एक ही व्यक्ति का दो भिन्न भिन्न नाम होने से नाम भिन्नता संबंध मे प्रमाण पत्र की मांग की गयी है जिससे उक्त प्रमाण पत्र हेतु मय आवेदन, शपथ पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, सेवा पुस्तिका की छाया प्रति सहित पेश किया गया है।

उक्त नाम भिन्नता प्रमाण पत्र संबंधित प्रकरण मे जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपत्ति दिनांक 08/02/2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी ।

आज दिनांक 24/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सील
**तहसीलदार**
भटगांव (छ0ग0)

## न्यायालय तहसीलदार अंबिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक: 202601020700105

**विषय:-अ-6 मामले की श्रेणी:- राजस्व सन्:-2025-26**

नमना कला प.ह.न. 00020 [607/1 (0.0030हे0) ]
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार-पवन सोनकर, अनावेदक पक्षकार -देवाशीष,सुभाष चन्द्र मुखर्जी,सुभाशीष,विजनचंद,

**ईश्तहार**

आवेदक पवन सोनकर आ0 (0) शिवनाथ सोनकर व अन्य निवासी नमनाकला तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने पिता पति के द्वारा क्रय की गई भूमि ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 607/1 रकबा 0.376 हे0 मेसे 1044 वर्गफीट भूमि के राजस्व अभिलेखो में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 13-06-2003 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 09.02.2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 15 01/2026 को जारी किया जाता है।

सील
**उमेश्वर सिंह बाज**
**तहसीलदार,अंबिकापुर**

# पति को ज़हर देकर मार डाला,बच्चों ने खोली पोल

-संवाददाता-
कोरबा,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है,जहां एक महिला ने अपने पति को ज़हर देकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद महिला ने इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की,लेकिन उसकी साजिश उस वक्त बेनकाब हो गई जब उसके मासूम बच्चों ने सच्चाई बयां कर दी।

यह पूरा मामला दर्री थाना क्षेत्र के लाटा बस्ती का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार,महिला ने पहले अपने पति को ज़हर दिया और फिर खुद ही उसे इलाज के बहाने अस्पताल लेकर पहुंची। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध आत्महत्या जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन पुलिस की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ।

महिला के बच्चों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी मां को पिता को ज़हर देते हुए अपनी आंखों से देखा है। बच्चों के इस बयान के बाद पुलिस ने बिना देर किए अस्पताल से ही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका किसी अन्य युवक के साथ प्रेम संबंध था,और इसी वजह से उसने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस को आशंका है कि इस हत्याकांड में महिला का प्रेमी भी शामिल हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला के प्रेमी की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

## कार्यालय वनमंडलाधिकारी,जशपुर वनमंडल,जशपुर (छत्तीसगढ़)

**नीलाम-सूचना**

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि जशपुर वनमण्डल के अन्तर्गत काष्ठागार गम्हरिया (जशपुर) में उपलब्ध निम्नांकित ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ का दर्शित तिथि एवं समय में ई-ऑक्शन द्वारा निर्वतन किया जावेगा। इच्छुक पंजीकृत व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि ई-ऑक्शन में अवश्य भाग लेवें । ई-आक्शन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय अथवा काष्ठागार गम्हरिया से प्राप्त की जा सकती है ।

डिपो का नाम - काष्ठागार गम्हरिया (जशपुर)
नीलाम दिनांक - 06/02.2026
नीलाम समय - 9.00 बजे प्रातः से

| प्रजाति | नीलाम में प्रस्तावित अनुमानित मात्रा | | | | | | मिश्रित जलाऊ चट्टा, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नया लाट | | पुराना लाट | | योग | | |
| | लट्ठा घ.मी. | बल्ली+ डेंगरी नग | लट्ठा घ.मी. | बल्ली+ डेंगरी नग | लट्ठा घ.मी. | बल्ली+ डेंगरी नग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| सागौन | 6.555 | 40 | 145.292 | 2659 | 151.847 | 2699 | पुराना |
| साल | 277.853 | 101 | 2275.416 | 7501 | 2553.269 | 7602 | 116 |
| बीजा, शीशम,खम्हार | 1.865 | 8 | 19.231 | 726 | 21.096 | 734 | नया |
| अन्य प्रजाति | 0.958 | 11 | 80.068 | 1586 | 81.026 | 1597 | 0 |
| चिरान काष्ठ | 1.148 | 0 | 2.418 | 0 | 3.566 | 0 | |
| योग | 288.379 | 160 | 2522.425 | 12472 | 2810.804 | 12632 | 116 |

उपरोक्त मात्रा में परिवर्तन संभावित है ।

टीप :-
01. क्रेताओं को ई-ऑक्शन के पूर्व एम. एस. टी. सी. ई - कॉमर्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है ।
02. क्रेताओं को ई-ऑक्शन के पूर्व क्रय लाटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वालेट में रखना अनिवार्य है । सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत ई. एम. डी. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
03. लाट की थप्पी एवं फोटो एम. एस. टी. सी. ई-ऑक्शन पोर्टल में अपने आई.डी. से लॉगईन करके देख सकते हैं ।
04. ई-ऑक्शन में लॉट क्रय के पश्चात् प्रथम क्रेता को 30 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा, उसी लॉट में अन्य क्रेताओं द्वारा 30 सेकण्ड के पूर्व क्रय करने पर 20 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा ।

जी नंबर-252606334/2

**वनमंडलाधिकारी**
( जशपुर वनमण्डल जशपुर)

CMYK

# कानून रक्षक ही कानून तोड़े तो कौन बचाएगा संविधान?

# अगर जुलूस ही न्याय है तो अदालतों की जरूरत क्या?

**अदालत से पहले सजा...**
बैकुंठपुर में छेड़छाड़ आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस

**जब पुलिस बनी जज...**
न्यायालय पहुंचने से पहले ही आरोपी को मिली 'सजा'

**कानून के नाम पर कानून की हत्या?**
आरोपी का जुलूस निकालने पर उठे सवाल

**संविधान या भीड़तंत्र?**
बैकुंठपुर की घटना ने पुलिस व्यवस्था पर खड़े किए प्रश्न

**दोष साबित होने से पहले**
हथकड़ी और अपमान...किस कानून में है यह प्रावधान?

**न्याय की जगह तमाशा:**
पुलिस की मौजूदगी में आरोपी का सार्वजनिक जुलूस

## अपराध दर्ज हुआ,फिर अदालत से पहले क्यों दी गई सजा?

## पुलिसिया न्याय या संवैधानिक अपराध? बैकुंठपुर मामला चर्चा में

## छेड़छाड़ केस में कानून लांघ गई पुलिस,आरोपी को बनाया भीड़ का शिकार

-रवि सिंह-

कोरिया,30 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

एक वीडियो वायरल होता है,पुलिस आरोपी को हथकड़ी पहनाकर सड़क पर घुमाती है, भीड़ मोबाइल निकालती है, सोशल मीडिया पर तालियां बजती हैं, लोग लिखते हैं –ठीक हुआ,ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। यही वह क्षण है, जब लोकतंत्र को सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए, क्योंकि जब न्याय तालियों पर चलने लगे, तो कानून की जरूरत खत्म होने लगती है।

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से सामने आई एक ताजा घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं, मामला महिला से छेड़छाड़ के आरोप से जुड़ा है, लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक वह तरीका है, जिस तरह पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने से पहले ही सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दिया, यह घटना अब केवल एक आपराधिक प्रकरण न रहकर संविधान,नागरिक अधिकार और पुलिसिया अधिकारों की सीमाओं पर बहस का विषय बन चुकी है,बैकुंठपुर की यह घटना केवल एक आरोपी का जुलूस नहीं थी, बल्कि यह उस खतरे का संकेत है,जहां न्याय से पहले अपमान,सुनवाई से पहले सजा और अदालत से पहले फैसला तय किया जाने लगा है, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, पुलिस का

नहीं,आज आवश्यकता है कि दोषियों को सजा मिले,पीड़ित को न्याय मिले,लेकिन संविधान और मानव गरिमा सुरक्षित रहे क्योंकि जब कानून की रक्षा करने वाला ही कानून तोड़ने लगे, तब लोकतंत्र सबसे ज्यादा संकट में होता है। पुलिस को सख्त होना चाहिए लेकिन निष्पक्ष होकर, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए लेकिन अदालत से,क्योंकि जिस दिन कानून तालियों से चलने लगे,न्याय कैमरे से तय होने लगे और पुलिस जज बन जाए,उस दिन अपराध नहीं बढ़ेगा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा,आज सवाल सिर्फ इतना है क्या हम न्याय चाहते हैं,या तमाशा?

### अब उठ रहा बड़ा सवाल

क्या पुलिस को अदालत से पहले सजा देने का अधिकार मिल गया है?

क्या कानून अब भीड़ और कैमरे के दबाव में चल रहा है?

क्या संविधान केवल किताबों तक सीमित रह गया है? यदि ऐसे मामलों पर समय रहते रोक नहीं लगी,तो कोई भी नागरिक कल इसी व्यवस्था का शिकार बन सकता है।

### क्या कानून जुलूस निकालने की अनुमति देता है?

संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना दोष सिद्ध हुए आरोपी को अपराधी की तरह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता,हथकड़ी का प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, किसी भी आरोपी का सार्वजनिक जुलूस निकालना अवैध है,सुप्रीम कोर्ट पूर्व में स्पष्ट कर चुका है कि पुलिस न्यायपालिका का स्थान नहीं ले सकती।

# जब भीड़ ताली बजाए और पुलिस जुलूस निकाले...तब संविधान चुप क्यों हो जाता है?

### जनता खुश है...लेकिन क्या यही न्याय है?

इस मामले में एक बड़ा वर्ग पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह सहमत है, लोगों का गुस्सा जायज है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, न्याय में देरी है, अपराधी अकसर बच निकलते हैं, लेकिन सवाल यह नहीं कि जनता खुश है या नाराज, सवाल यह है क्या कानून जनता की भावना से चलेगा या संविधान से? अगर गुस्से से ही न्याय तय होना है, तो अदालतें बंद कर दीजिए।

### अगर जुलूस सही है,तो हर अपराध में क्यों नहीं?

यहां सबसे असहज सवाल खड़ा होता है अगर पुलिस द्वारा आरोपी का जुलूस निकालना ठीक है,तो यह नियम सबके लिए क्यों नहीं? अशफाक उल्ला जैसे बड़े मामलों में जुलूस क्यों नहीं निकला? कुलदीप जैसे संगीन अपराधों में सड़क पर घुमाकर क्यों नहीं दिखाया गया? सफेदपोश अपराधियों पर यह साहस क्यों नहीं दिखा? क्यों? क्योंकि वहां सत्ता थी,वकालत थी,पहचान थी,यहां कुछ भी नहीं था।

### क्या पुलिस केवल कमजोर पर बहादुर है?

यही वह जगह है जहां पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आती है,क्या कानून अब यह तय करेगा,किसके पास पहुंच है,किसके पास पैसा है,किसके पास राजनीतिक छाया है और उसी हिसाब से तय होगा कि किसका जुलूस निकलेगा और किसे सम्मानपूर्वक थाने से अदालत भेजा जाएगा? अगर ऐसा है, तो इसे कानून मत कहिए...इसे चयनात्मक ताकत कहिए।

### न्याय नहीं, प्रदर्शन हो रहा है...

यह भी सच है कि जुलूस से अपराध नहीं रुकते,कैमरे से कानून मजबूत नहीं होता, अपमान से न्याय नहीं मिलता,लेकिन यह जरूर होता है पुलिस का कंधा थपथपाया जाता है,कुछ घंटे की वाहवाही,कुछ हजार लाइक्स,कुछ वायरल वीडियो,न्याय नहीं,सिर्फ प्रदर्शन।

### संविधान अपराधियों को नहीं,नागरिकों को बचाता है

अक्सर कहा जाता है संविधान अपराधियों का पक्ष लेता है। यह झूठ है,संविधान अपराधी को नहीं,नागरिक को बचाता है,क्योंकि आज आरोपी नागरिक है,कल वही कानून आपको भी बचाएगा, अगर अदालत से पहले सजा मिलने लगे,तो निर्दोष होने का अधिकार खत्म हो जाएगा।

### डर से नहीं,न्याय से समाज चलता है...

इतिहास गवाह है की डर से अपराध कभी खत्म नहीं हुए, फांसी से अपराध बंद नहीं हुए, लाठी से समाज सभ्य नहीं बना, सभ्य समाज बना –निष्पक्ष जांच से, त्वरित न्याय से और समान कानून से बाकी सब सिर्फ तात्कालिक संतोष है।

### आज सवाल एक जुलूस का नहीं है...

यह बहस आरोपी की नहीं है,यह बहस पुलिस की भी नहीं है,यह बहस उस सीमा की है,जहां से आगे जाकर कानून भीड़ बन जाता है, आज अगर हम खुश हैं कि उसका जुलूस निकला, तो कल जब बिना सुनवाई हमारा नाम आए –तो हमें बचाने कोई नहीं बचेगा।

### आज आरोपी, कल कौन?

आज जिसे लोग गालियां दे रहे हैं,कल वही तरीका किसी निर्दोष पर भी लागू हो सकता है,क्योंकि जब प्रक्रिया खत्म होती है, तो सुरक्षा भी खत्म हो जाती है,आज भीड़ कह रही है 'इसे घुमाओ।' कल वही भीड़ कहेगी –'इसे भी घुमाओ।' फर्क सिर्फ नाम का होगा।

### छेड़छाड़ का मामला, एफआईआर दर्ज

यहां तक सब ठीक-प्राप्त जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर क्षेत्र में एक युवक पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, पीड़िता ने साहस दिखाते हुए थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया, अपराध दर्ज होना कानून सम्मत प्रक्रिया है और यह स्पष्ट करता है कि पुलिस ने प्रारंभिक स्तर पर अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन इसके बाद जो दृश्य सामने आया, उसने पूरे मामले को विवादों के घेरे में ला खड़ा किया।

### संविधान की रक्षा या भीड़ का मनोरंजन?

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि लोग तमाशबीन बने रहे,वीडियो मनोरंजन की तरह साझा किए गए और संविधान खतरे में है कहने वाले कई वर्ग इस मामले में मौन रहे, विशेषज्ञों का मानना है कि जब न्याय भीड़ के हाथों सौंप दिया जाता है,तब लोकतंत्र कमजोर होता है।

### महिला सम्मान जरूरी,लेकिन कानून से समझौता नहीं

यह स्पष्ट है कि महिला से छेड़छाड़ गंभीर अपराध है, दोषी को कठोर सजा मिलनी चाहिए,लेकिन न्याय की प्रक्रिया कानून से बाहर जाकर नहीं चल सकती,यदि आरोपी दोषी है तो अदालत उसे दंड देगी,लेकिन यदि पुलिस ही अदालत बनने लगे तो यह व्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत है।

### कानून विशेषज्ञों की राय

वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि इस प्रकार का जुलूस मानवाधिकारों का उल्लंघन है,इससे मुकदमे की निष्पक्षता भी प्रभावित होती है,आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है,ऐसे मामलों में संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं न्यायिक कार्रवाई का प्रावधान है। जब भीड़ ताली बजाए और पुलिस जुलूस निकाले – तब संविधान चुप क्यों हो जाता है?

### न्यायालय पहुंचने से पहले ही सजा

जब पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए ले जा रही थी,उसी दौरान आरोपी को सार्वजनिक रूप से हथकड़ी पहनाई गई, बाजार और सार्वजनिक रास्तों से उसे जुलूस की तरह घुमाया गया, राहगीरों और भीड़ के सामने उसका अपमान किया गया,इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया गया,यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ,जिसके बाद मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया, विडियो में यह भी दिखाई देता है कि पुलिस की मौजूदगी में भीड़ तमाशबीन बनी रही और कथित तौर पर महिला को आरोपी को थप्पड़ मारने के लिए उकसाया गया।

### दोष सिद्ध हुए बिना सार्वजनिक अपमान

कानून के जानकारों का कहना है कि आरोपी दोषी है या निर्दोष,यह तय करने का अधिकार केवल न्यायालय को है, पुलिस जांच कर सकती है,सजा नहीं दे सकती,अदालत से पूर्व इस प्रकार का सार्वजनिक अपमान पूर्व-दंड (Pre-Punishment) की श्रेणी में आता है, यह न केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) बल्कि भारत के संविधान का भी उल्लंघन माना जाता है।

### छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

ऐसे ही एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में दुर्ग जिले के भिलाई थाना क्षेत्र में हुई पुलिसिया कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया है, Case Title: Sujeet Sao and Others v. State of Chhattisgarh and Others WPCR No. 11 of 2026 इस प्रकरण में आरोपियों का जुलूस निकालने और कथित रूप से प्रताड़ित करने के मामले में हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी (SHO),सीएसपी,पुलिस अधीक्षक,प्रधान आरक्षक,एएसआई,आरक्षक सहित 09 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जांच के आदेश जारी किए हैं।

### हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा ये ऐसे मामले हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के मूल ढांचे पर सीधा प्रहार करते हैं, कोर्ट ने आगे कहा कि प्रत्येक नागरिक को जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार प्राप्त है, पुलिस हिरासत में किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या अपमान अस्वीकार्य है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में नागरिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह पुलिसिया ज्यादती और कानून के शासन की अवहेलना मानी जाएगी।

CMYK

# पीरियड्स में झाड़ियों के पीछे बदलते थे पैड्स

**चादर लेकर खड़े रहते थे लोग, जया बच्चन ने बताया कैसे थे हालात**

आज के समय में एक्ट्रेसेस के पास भले ही सारी सुविधा हो, लेकिन टाइम ऐसा था, जब उनके पास कोई वैनिटी वैन नहीं थीं। आउटडोर शूट्स पर तो 60-70 के दशक की एक्ट्रेसेस ने क्या-क्या झेला, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जया बच्चन ने नाती नव्या नंदा से एक किस्सा शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पीरियड्स के दिनों में एक सैनेटरी पैड बदलना कितना मुश्किल था।

आज के समय में फिल्मी सितारों के पास हर चीज की सुविधा है। जब भी एक्टर्स शूट से थक जाते हैं, तो अपनी वैनिटी वैन में एसी ऑन करके थोड़ी देर थोड़ा सुस्ता लेते हैं। उस वैनिटी वैन में उनके लिए हर चीज की सुविधा होती है।

हालांकि,1991 से पहले समय काफी अलग था। पूनम ढिल्लों के फर्स्ट टाइम वैनिटी का कल्चर लाने से पहले एक्ट्रेसेस को सेट पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। खास तौर पर अभिनेत्रियों को कपड़े चेंज करने में दिक्कत आती थीं। दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने आउटडोर शूट करते हुए पीरियड के दिनों का एक ऐसा ही थ्रोबैक किस्सा सुनाया था, जिसे सुनकर उनकी नाती नव्या हैरान रह गई थीं।

**झाड़ियों के पीछे अभिनेत्रियां बदलती थीं पैड्स**

गुड्डी एक्ट्रेस जया बच्चन ने नाती नव्या नंदा के शो में एक ऐसा ही सेट पर असहज करने वाले मोमेंट के बारे में बताया था। जब वह नव्या नंदा के शो व्हाट द हेल नव्या में खास मेहमान बनकर आई थीं, तो उन्होंने 70-80 के दशक की अभिनेत्रियों के शूटिंग के दौरान रियल संघर्ष के बारे में उन्हें समझाया था।

जया ने शूटिंग सेट पर अपने टीनेज समय को याद करते हुए कहा, जब हम आउटडोर शूट्स करते थे, तब हमारे पास वैनिटी वैन्स नहीं होती थी। हमें झाड़ियों के पीछे ही कपड़े बदलने पड़ते थे, जहां 4 से 5 लोग चादर के साथ खड़े होते । हर चीज वैसे ही करनी पड़ती थी। आउटडोर शूट्स पर ज्यादा टॉयलेट्स भी नहीं बने थे। यह बहुत ही असुविधाजनक और शर्मनाक था। तब एक्ट्रेसेस एक बार में 3-4 सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती थीं और अपने साथ एक प्लास्टिक बैग कैरी करती थीं। वह उस बैग को बास्केट में रखती थीं,ताकि जब वह घर जाएं तो उसे फेंक सके।

**4-5 सैनिटरी पैड्स के साथ बैठना होता है मुश्किल**

जया बच्चन ने नव्या नंदा के साथ थ्रो-बैक इंटरव्यू में आगे कहा था,हमारे समय में आज वाले सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे,जो चिपक जाए। सोचों उस समय चार-पांच पैड्स लगाकर बैठना कितना ज्यादा मुश्किल होता था। वह बहुत ही अनकम्फर्टेबल कर देता था। आपको दोनों एंड्स पर बेल्ट लगानी पड़ती थी,क्योंकि पैड में लूप होते थे,उसे टेप से स्टिक करना पड़ता था। वह बहुत ही बुरा समय था।

जया बच्चन के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1963 में बंगाली फिल्म महानगर के साथ एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उनकी साल 1971 में रिलीज हुई पहली हिंदी फिल्म गुड्डी एक बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने उपहार, बावर्ची, जंजीर जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया।

# मेरी और उसकी उम्र में अंतर...गौरव खन्ना संग डिवोर्स रूमर्स पर बोलीं पत्नी आकांक्षा चमोला

बिग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला के तलाक की अफवाहें आकांक्षा के एक क्रिप्टिक पोस्ट के बाद उड़ी थीं। अब आकांक्षा ने इस बात पर रिएक्ट करते हुए अपना पक्ष रखा है। आकांक्षा ने कहा कि अभी मां न बनने का उनका निजी फैसला है, जिसके लिए उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना और उनकी पत्नी के बीच कुछ अनबन चल रही है। इसकी वजह आकांक्षा चमोला का एक पोस्ट था। कहा तो ये तक जा रहा था कि दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं।

**आकांक्षा ने रिश्तों पर की थी बात**

दरअसल आकांक्षा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बात लिख दी थी जिसके बाद से ऐसे रूमर्स आए थे। अब इस मामले में आकांक्षा चमोला ने अपनी बात रखी है। आकांक्षा ने साफ किया कि उनके और गौरव खन्ना के बीच सबकुछ ठीक है और ऐसी कोई बात नहीं है। आकांक्षा ने लिखा था, ÷जिस रिश्ते की बुनियाद में सिर्फ जरूरतें हों वहां हमेशा दिल कुर्बाना होता है।

**गलत अर्थ निकाला गया:आकांक्षा**

आकांक्षा ने बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में कहा, हमारी शादीशुदा जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, और उस पोस्ट का गौरव से कोई लेना-देना नहीं था। मैं सोशल मीडिया पर अपने पर्सनल मैटर डिस्कस नहीं करती। मैंने वो पोस्ट अपनी अपकमिंग सीरीज के प्रचार के लिए की थी। इसका अलग-अलग अर्थ निकाला जा सकता था, लेकिन इसे बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।

**मां बनने पर आकांक्षा ने की बात**

आकांक्षा ने आगे कहा,इस समय तो मैं ही ट्रोल क्वीन बनी हुई हूं! मैं इस विषय पर हमेशा खुलकर बोलती रही हूं। गौरव थोड़ा सतर्क रहता है क्योंकि वह मेरी इमेज को बचाना चाहता है। हम दोनों की उम्र में अंतर है, और वह काफी समझदार है कि मेरे प्वाइंट को अच्छे से समझते हैं। मैंने साफ तौर पर कहा है कि मैं अभी मां नहीं बनना चाहती। यह मेरा निजी फैसला है और मुझे किसी के सामने इसे सही ठहराने की जरूरत नहीं है। आकांक्षा को अपनी पोस्ट के बाद ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। कई लोग उन्हें इसलिए ट्रोल कर रहे थे कि गौरव पिता बनना चाहते हैं जबकि आकांक्षा अभी ऐसा नहीं चाहती और इस वजह से दोनों अलग हो रहे हैं। आकांक्षा संतोषी मां, क्राइम पेट्रोल और ये है आशिकी जैसे सीरियलों में काम कर चुकी हैं।

# 16 की एक्ट्रेस,24 का हीरो,टीवी सीरियल में इंटीमेट सीन देख भड़के लोग,कहा...नाबालिग के साथ और क्या ये लीगल भी है?

टीवी शो रिमझिम-छोटी उम्र बड़ा सफर एक नए विवाद में घिर गया है। 16 साल की अभिनेत्री यशिका शर्मा और 24 साल के हिमांशु अवस्थी के बीच दिखाए गए इंटीमेट सीन पर दर्शक भड़क गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग नाबालिग के साथ ऐसे दृश्यों की नैतिकता और कानूनी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। एक खास सीन, जिसमें नायक नायिका को करीब खींचता है, वायरल हो गया है, जिससे मेकर्स की आलोचना हो रही है।

टीवी की दुनिया में अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है कि फैंस का दिमाग जरूर घूम जाता है। कभी इन टीवी शोज की कहानी को लेकर चर्चा होती है तो कभी सीन को लेकर विवाद हो जाता है। अब लीजिए एक और नए टीवी सीरियल को लेकर इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है और वजह है 16 साल की एक्ट्रेस का अपने मेल को-स्टार के साथ रोमांस। अब क्या है ये नया विवाद, आइए आपको बताते हैं...

**टीवी शो में ये कैसा रोमांस?**

दरअसल टीवी शो रिमझिम-छोटी उम्र बड़ा सफर इस वक्त काफी चर्चाओं में है। अब इसी बीच यह शो एक बड़े विवाद में फंस गया है। सोशल मीडिया पर लोग इस शो की काफी आलोचना कर रहे हैं।

हुआ ये कि,शो के हाल ही के एक एपिसोड में नाबालिग (16 साल की) एक्ट्रेस और उनके को-स्टार (24 साल) के बीच कुछ इंटीमेट सीन टीवी पर दिखाए गए।

इसके बाद लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि शो की लीड एक्ट्रेस यशिका शर्मा सिर्फ 16 साल की हैं, जबकि उनके साथ रोमांस करने वाले एक्टर हिमांशु अवस्थी 24 साल के हैं। ऐसे में एक कम उम्र की लड़की के साथ बड़े उम्र के हीरो के रोमांटिक सीन दिखाने की वजह से इस शो का विरोध हो रहा है।

**क्या था वो सीन, जिस पर हुआ विवाद?**

दरअसल 28 जनवरी को दंगल टीवी पर प्रसारित हुए इस शो के एपिसोड के एक सीन में दिखाया गया है जहा समीर (हिमांशु) रिमझिम (यशिका) के सामने अपनी शर्ट उतारता है, उसे अपने करीब खींचता है। रिमझिम के ब्लाउज की डोरी के खुलने से वो सहम जाती है तो फिर समीर उसे अपनी शर्ट पहना देता है।

इस सीन में दोनों की रोमांटिक कैमिस्ट्री दिखाने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी इस शो के एक सीन पर विवाद हुआ था और अब इस नए सीन पर घमासान मच गया है। रेडिट पर यूजर्स ने कहा है कि, आखिर किस दुनिया में एक 15-16 साल की बच्ची का ऐसे इंटिमेट सीन शूट करना सही माना जाता है? तो वहीं कई और यूजर्स ने भी इस पर ऐतराज जताया है।

## खेल समाचार

# नोवाक जोकोविच 11वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में

**वर्ल्ड नंबर-1 कार्लोस अल्काराज होगा मुकाबला; सिनर को 3-6,6-3,4-6,6-4, 6-4 से हराया**

**सर्बिया,30 जनवरी 2026।**

सर्बिया के दिग्गज टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने साल के पहले ग्रैंडस्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जहां उसका सामना वर्ल्ड नंबर-1 कार्लोस अल्काराज से एक फरवरी को दोपहर 2 बजे से होगा। 38 साल के जोकोविच ने मेंस सिंगल्स कैटेगरी के सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन जैनिक सिनर को 3-6, 6-3, 4-6,6-4,6-4 से हराया।

जोकोविच ने 11वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। वे 2023 के बाद खिताबी दौर में पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने 10 फाइनल खेले और सभी जीते हैं। जोकोविच अपने करियर के 25वें ग्रैंड स्लैम और 11वें ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल से एक जीत दूर हैं। फिलहाल वे मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड की बराबरी पर हैं।

**अल्काराज पहली बार फाइनल में पहुंचे**

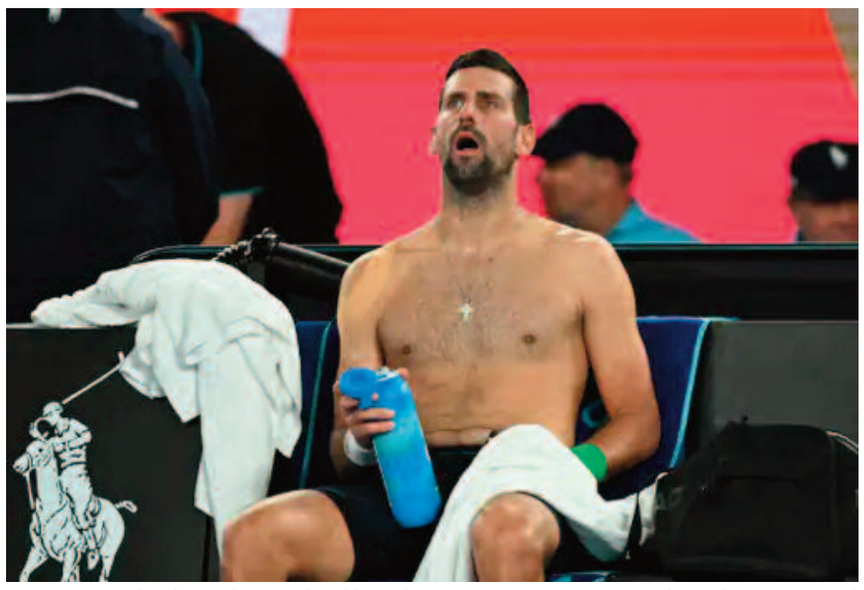

वर्ल्ड नंबर-1 स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। चोट से जूझ रहे अल्काराज ने सेमीफाइनल में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को पांच सेटों तक चले मुकाबले में मात दी। मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में खेला गया यह मैच 5 घंटे 27 मिनट तक चला, जिसमें अल्काराज ने ज्वेरेव को 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 से हराया।

**अल्काराज बोले...मुझे खुद पर बेहद गर्व है...**

जीत के बाद अल्काराज ने कहा...मैं हमेशा कहता हूं कि हालात चाहे जैसे भी हों, खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। तीसरे सेट में मैं संघर्ष कर रहा था। शारीरिक रूप से यह मेरे करियर के सबसे कठिन मुकाबलों में से एक था।

उन्होंने कहा...'मैं पहले भी ऐसे मैच खेल चुका हूं, इसलिए मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे इसमें दिल-जान लगा देनी थी। मैंने ऐसा ही किया और आखिरी गेंद तक लड़ता रहा। पांचवें सेट में जिस तरह से मैंने वापसी की,उस पर मुझे खुद पर बेहद गर्व है।'

**अल्काराज के पास करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने का मौका**

अल्काराज के ट्रॉफी कैबिनेट में अब तक का एकमात्र ग्रैंड स्लैम खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन ही बचा है। अगर वह इस साल मेलबर्न में जीत हासिल करते हैं, तो वह करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के मेंस प्लेयर बन जाएंगे।

करियर ग्रैंड स्लैम का मतलब है कि किसी खिलाड़ी ने अपने पूरे करियर के दौरान चारों ग्रैंड स्लैम कम से कम एक बार जीती हों। इन्हें एक ही कैलेंडर ईयर में जीतना जरुरी नहीं है।

**विमेंस फाइनल में सबालेंका व्हीएस रायबकिना**

विमेंस सिंगल्स फाइनल में आर्यना सबालेंका का सामना एलिना रायबकिना से होगा। यह मैच रॉड लेवर एरिना में 31 जनवरी को दोपहर 2:00 बजे से खेला जाएगा। टॉप सीड सबालेंका ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन की विमेंस सिंगल कैटेगरी के सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराया।

# आईसीसी ने ग्रूप स्टेज के लिए 24 मैच अधिकारियों की घोषणा की

**दुबई,30 जनवरी 2026।** इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शुक्रवार को 7 फरवरी से शुरू होने वाले पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज के लिए मैच अधिकारियों की घोषणा की। कुल मिलाकर,24 अधिकारी ऑन-फील्ड अंपायर के रूप में काम करेंगे, और छह आईसीसी पुरुष टी 20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रूप स्टेज के दौरान मैच रेफरी होंगे। सुपर आठ और नॉकआउट स्टेज के लिए अधिकारियों की घोषणा बाद में की जाएगी। कुमार धर्मसेना और वेन नाइट्स कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच शुरुआती मैच में ऑन-फील्ड अंपायर होंगे।

यह मैच नाइट्स का आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में पहला मैच होगा, जबकि धर्मसेना अपने बड़े टूर्नामेंट अनुभव को और बढ़ाएंगे। धर्मसेना 1996 में श्रीलंका की आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने आईसीसी पुरुष टी 20 वर्ल्ड कप में 37 मैचों में अंपायरिंग की है, जिसमें 2016 और 2022 के फाइनल शामिल हैं। यह उपलब्धि उन्हें इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वालों की ऑल-टाइम लिस्ट में चौथे स्थान पर रखती है।

नाइट्स भी ग्रूप ए मैच के दौरान एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करेंगे,क्योंकि वह ऑन-फील्ड अंपायर के रूप में अपना 50वां टी 20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। कोलकाता में पहले दिन, नितिन मेनन और सैम नोगजस्की स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज के बीच ग्रूप सी मैच की जिम्मेदारी संभालेंगे। मेनन 2024 पुरुष टी 20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच ऑन-फील्ड अंपायर टीम का हिस्सा थे। नोगजस्की ने पिछले एडिशन में चार ग्रुप मैचों में अंपायरिंग की थी, जिसमें भारत का यूएसए के खिलाफ मैच भी शामिल था। भारत और यूएसए 7 फरवरी को मुंबई में मिलेंगे,जिसमें पॉल राइफल और रॉड टकर को

ऑन-फील्ड अंपायर नियुक्त किया गया है। टकर के नाम आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड है,अब तक 46 मैच। वह टूर्नामेंट के दौरान अपना 50वां मैच पूरा करने वाले हैं। यह ऑस्ट्रेलियाई अंपायर इंग्लैंड बनाम नेपाल,भारत बनाम नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका बनाम संयुक्त अरब अमीरात जैसे मैचों में भी अंपायरिंग करेंगे। क्रिस गैफ़नी और रिचर्ड इलिंगवर्थ, जिन्होंने 2024 के फ़ाइनल में एक साथ काम किया था, वे 11 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच ग्रूप क़मैच के लिए फिर से साथ आएंगे। इलिंगवर्थ 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण ग्रूप-स्टेज मैच में धर्मसेना के साथ ऑन-फील्ड भी होंगे।

**मैच रेफरी:**-डीन कॉस्कर,डेविड गिल्बर्ट,रंजन मदुगले,एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट,रिची रिचर्डसन,जवागल श्रीनाथ।

**अंपायर:**- रोलैंड ब्लैक,क्रिस ब्राउन, कुमार धर्मसेना, क्रिस गैफ़नी, एड्रियन होल्डस्टॉक, रिचर्ड इलिंगवर्थ,रिचर्ड केटलबोरो,वेन नाइट्स, डोनोवन कोच,जयरामन मदनगोपाल,नितिन मेनन, सैम नोगजस्की,केएनए पद्मनाभन,अल्लाहुद्दीन पालेकर,अहसान रज़ा,लेस्ली रीफ़र,पॉल रीफ़ेल, लैंगटन रुसेरे,शरफुद्दौला इब्ने शाहिद,गाज़ी सोहेल, रॉड टकर,एलेक्स वार्फ,रवींद्र विमलसिरी, आसिफ याकूब।

# श्रीवल्ली भामिदिपति ने साझा किया सफलता का राज

**मुंबई,30 जनवरी 2026।** 24 साल की लगातार जीतने वाली और भारत की नंबर तीन महिला सिंगल्स खिलाड़ी, श्रीवल्ली भामिदीपति को आने वाले मुंबई ओपन डब्ल्यूटीए 125 के सीरीज़ के मेन ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड दिया गया है, जो मुंबई में महाराष्ट्र स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन में होगा। क्वालिफायर 31 जनवरी-1 फरवरी को होंगे, जिसके बाद मेन ड्रॉ होगा, जो 2-8 फरवरी, 2026 तक होना तय है। श्रीवल्ली भामिदीपति ने इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी जीत हासिल करके खुद को भारतीय टेनिस में एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर स्थापित किया है। उन्होंने 2023 डब्ल्यू 25 बेंगलुरु इवेंट में अपना पहला इंटरनेशनल टेनिस

फेडरेशन सिंगल्स टाइटल जीता और 2024 में करियर की सबसे अच्छी डब्ल्यूटीए रैंकिंग नंबर 300 पर पहुंचीं। 2025 में उनकी शोहरत और बढ़ी जब वह एशिया/ओशिनिया ग्रुप 1 के लिए बिली जीन किंग कप हार्ट अवॉर्ड जीतने वाली सिर्फ तीसरी भारतीय महिला बनीं। उन्होंने मुंबई ओपन के पिछले एडिशन में क्वार्टर-फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए कई शानदार परफॉर्मेंस भी दिए। श्रीवल्ली ने राउंड ऑफ़ 32 में रूसी खिलाड़ी एलेना प्रिडांकिना को हराया, दो सीधे सेट जीतकर मैच को एक घंटे के अंदर खत्म कर दिया। उन्होंने राउंड ऑफ़ 16 में विस्फोटक सर्बियाई राइट-हैंडर,एलेक्जेंड्रा क्रूनिक के खिलाफ भी अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और क्वार्टर-फाइनल स्टेज में पहुंचीं। उनका शानदार सफर यहीं खत्म हो गया क्योंकि उन्हें आखिरकार चैंपियन बनी जिल टीचमैन के हाथों हार का सामना करना पड़ा और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गईं।

# यूएई टीम का नेतृत्व करेंगे वसीम मेंस

**अराफात होंगे फास्ट बॉलिंग कोच**

**नई दिल्ली,30 जनवरी 2026।** यूएई के स्टार बैटर मुहम्मद वसीम 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले 2026 आईसीसी पुरुष टी 20 वर्ल्ड कप में 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी करेंगे। यूएई ने पिछले साल ओमान में एशिया और ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालिफायर के सुपर सिक्स स्टेज में जापान को हराकर 20 टीमों के टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की की थी। यह टीम पहले भी 2014 और 2022 में इस बड़े इवेंट में दो बार खेल चुकी है - दोनों बार ग्रूप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। वर्ल्ड कप से पहले, यूएई आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी 20आई सीरीज़ खेल रहा है, जिसके बाद 3 और 6 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में नेपाल और इटली के खिलाफ वार्म-अप मैच खेलेगा।

उनका ग्रूप डी का अभियान 10 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होगा,जिसके बाद वे नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कनाडा (13 फरवरी), अफगानिस्तान (16 फरवरी) और दक्षिण अफ्रीका (18 फरवरी) का सामना करेंगे। टीम में यूएई के 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुए पिछले टी 20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले तीन खिलाड़ी शामिल हैं-वसीम, अलीशान शराफू और जुनैद सिद्दीकी। वसीम, जो पिछले तीन सालों से टीम की कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने अपने 92 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से 66 में यूएई की कप्तानी की है। हेड कोच, पूर्व भारतीय खिलाड़ी लालचंद राजपूत के नेतृत्व वाले सपोर्ट स्टाफ में, पूर्व पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ यासिर अराफात तेज़ गेंदबाज़ी कोच के रूप में शामिल हुए हैं,जबकि ज़िम्बाब्वे के स्टेनली चियोज़ा फील्डिंग कोच के रूप में काम करेंगे।

अराफात, जिन्होंने सभी फॉर्मेट में 27 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है, कई राष्ट्रीय टीमों और फ्रेंचाइजी को कोचिंग दे चुके हैं। वह आयरलैंड सीरीज़ और उसके बाद होने वाले टी 20 वर्ल्ड कप के दौरान यूएई टीम के साथ रहेंगे।

**यूएई टीम:**- मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, आर्यन शर्मा (विकेटकीपर),ध्रुव पराशर,हैदर अली,हर्षित कौशिक,जुनैद सिद्दीकी,मयंक कुमार,मुहम्मद अरफान,मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह,मुहम्मद जोहैब,रोहिद खान,सोहैब खान और सिमरनजीत सिंह।

CMYK

# छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बड़ा हल्लाबोल...

## धान खरीदी और मनरेगा को लेकर प्रदेशव्यापी चक्काजाम,सड़कों पर उतरे दिग्गज...

**रायपुर,30 जनवरी 2026।** छत्तीसगढ़ की राजनीति में उस समय उबाल आ गया जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तर पर 'मनरेगा बचाओ संग्राम' का बिगुल फूँक दिया। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ जैसे प्रमुख जिलों समेत राज्य के लगभग हर ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों का विरोध करना और राज्य सरकार से धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग करना था। सड़कों पर उतरे कांग्रेसी नेताओं ने चक्काजाम कर शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

### मनरेगा के अस्तित्व पर संकटः एक में बदलाव और नाम बदलने का कड़ा विरोध...

कांग्रेस के इस बड़े आंदोलन के केंद्र में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून' है। विपक्षी दल का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार इस ऐतिहासिक कानून के मूल स्वरूप को खत्म कर 'VB-G RAM G' के नाम से एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में है। इसे लेकर मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है।

### धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग,किसानों के नुकसान की जताई आशंका

आंदोलन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू किसानों से जुड़ी धान खरीदी की समस्या है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने पुरजोर मांग की है कि धान खरीदी की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस का तर्क है कि अब भी राज्य के एक बड़े हिस्से में बहुत से किसान ऐसे हैं,जो तकनीकी कारणों या अन्य असुविधाओं के चलते अपना पूरा धान नहीं बेच पाए हैं। यदि समय सीमा नहीं बढ़ाई गई,तो इन किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। रायगढ़ और दुर्ग जैसे कृषि प्रधान जिलों में इस मांग को लेकर जबरदस्त चक्काजाम देखने को मिला,जिससे यातायात भी काफी प्रभावित हुआ।

कांग्रेसियों का कहना है कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके नाम या एक्ट में किसी भी प्रकार का बदलाव गरीबों के अधिकारों पर हमला है। इसी मुद्दे को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए।

### रायगढ़ में शराब दुकान के सामने प्रदर्शन ड्राई डे घोषित न करने पर जताया आक्रोश...

रायगढ़ जिले के कोलाईबहाल और जामगांव क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन का एक अलग ही रूप देखने को मिला। यहाँ कोलाईबहाल-जामगांव ओडिशा रोड पर चक्काजाम करने के साथ ही कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 'ड्राई डे' (मद्य निषेध दिवस) घोषित नहीं किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। कार्यकर्ताओं ने शराब की दुकान के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और सरकार की नीति पर सवाल उठाए। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि बापू की पुण्यतिथि पर शराब की दुकानों का खुला रहना उनकी विचारधारा और सिद्धांतों का अपमान है।

### दुर्ग और अन्य जिलों में सांकेतिक चक्काजाम : जमीनी स्तर पर लामबंदी

दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस ने 'अंडा' गांव के अटल चौक पर अपना डेरा डाला। यहाँ बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक चक्काजाम कर आवाजाही रोक दी। मंच से संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने और मनरेगा को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। इसी तरह रायपुर और बिलासपुर में भी शहर से लेकर गांव तक कांग्रेस की सक्रियता नजर आई। जिला और शहर कांग्रेस के तमाम छोटे-बड़े पदाधिकारियों ने इस आंदोलन में शिरकत की,जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि आने वाले दिनों में रोजगार और कृषि के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासी तपिश और बढ़ने वाली है।

### रामानुजगंज में एक घंटे तक चक्काजाम

रामानुजगंज में कांग्रेस ने किसानों और आम जनता की मांगों को लेकर महावीरगंज चौक पर एक घंटे तक चक्का जाम किया। ब्लॉक अध्यक्ष मधु गुप्ता के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम तहसीलदार के माध्यम से मांग पत्र सौंपा। इसमें धान खरीदी की तिथि बढ़ाने,मनरेगा कानून को पूर्ववत लागू करने और पीडीएस में चावल की कमी दूर करने की मांग की गई। प्रशासन ने समझाइश के बाद जाम समाप्त करवाया और मांगें उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

### गरियाबंद में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा

गरियाबंद में कांग्रेस ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क जाम किया। देवभोग में धान की बोरिया लेकर और मैनपुर में NH-130C जाम कर कांग्रेसियों ने नारेबाजी की। वाहनों की कतार लगने के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपकर चक्काजाम स्थगित किया गया।

# छत्तीसगढ़ के सुकमा में चार माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

**सुकमा,30 जनवरी 2026।** छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले के किस्टाराम एरिया कमेटी में सक्रिय 8 लाख रुपये के इनामी चार माओवादी कैडरो ने शुक्रवार को ऑटोमैटिक हथियार पुलिस अधिकारियों को सौंप कर आत्मसमर्पण किया है। इनमें दो महिला नक्सली शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुकमा पुलिस एवं आंध्र प्रदेश के अल्लूरि सीताराम राजू जिला पुलिस के संयुक्त प्रयासों से'पूना मारगेम-पुनर्वास से पुनर्जीवन' अभियान के अंतर्गत बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टलिंगम,पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चव्हाण,पंकज मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अल्लूरि सीताराम राजू (आंध्रप्रदेश),रोहित शाह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुकमा, 21सी कोंटा रेंज सीआरपीएफ अरविंद पी. आनंद के समक्ष दक्षिण बस्तर डिविजन अंतर्गत कोंटा किस्टाराम एरिया कमेटी में सक्रिय कुल 8 लाख रुपये के इनामी चार माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों में एसीएम सोढ़ी जोगा,निवासी सिंघनमड़गू,थाना किस्टाराम,जिला सुकमा,डाबर गंगा उर्फ मड़कम गंगा निवासी सिंगाराम,गोलापल्ली,सोढ़ी राजे गोलापल्ली एलओएस सदस्य निवासी एंटापाड़,थाना चिंतागुफा, जिला सुकमा और माड़वी बुधरी,गोलापल्ली एलओएस सदस्य निवासी सिंघनमड़गू,थाना किस्टाराम,जिला सुकमा शामिल हैं। इनमें सोढ़ी जोगा पर पांच लाख रुपये का इनाम है। इसके अलावा डाबर गंगा पर एक लाख,सोढ़ी राजे पर एक लाख और माड़वी बुधरी पर एक लाख रुपये का इनाम है। इन लोगों ने अपनी एसएलआर रायफल सहित कई खतरनाक हथियार पुलिस को सौंप दिए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सुकमा किरण चव्हाण ने कहा कि हम शेष बचे माओवादी कैडरों से भी अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें और शासन की पुनर्वास योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करें।

# एम्बुलेंस बनी नशे की खेप ढोने का जरिया...रायपुर रेंज पुलिस ने 520 किलो गांजा पकड़ा,9 तस्कर गिरफ्तार

**रायपुर,30 जनवरी 2026।** नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में रायपुर रेंज पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक हाथ लगी है। ऑपरेशन 'निश्चय' के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और महासमुंद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एम्बुलेंस से तस्करी किया जा रहा 520 किलो अवैध गांजा जब्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र में की गई,जहां ओडिशा से महाराष्ट्र तक फैले अंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क को तोड़ते हुए थोक खरीदार,परिवहन सरगना और सप्लायर समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि तस्कर पुलिस की नजरों से बचने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे और गांजा ओडिशा से महाराष्ट्र के पुणे इलाके तक पहुंचाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में सप्लाई चेन की हर कड़ी बैकवर्ड लिंक सप्लायर से लेकर फॉरवर्ड लिंक खरीदार तक का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पुणे निवासी रामदास चंदू सोनवाने को मुख्य थोक खरीदार बताया गया है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। उसके साथ उसके दोनों बेटे भी गांजा वितरण नेटवर्क में सक्रिय पाए गए हैं। पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़ी करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्तियों की पहचान की है,जिन्हें SAFEMA के तहत अटैच करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं, ओडिशा से महाराष्ट्र तक गांजा परिवहन का संचालन करने वाले मुख्य सरगना आकाश जाधव को भी गिरफ्तार किया गया है, जो सोशल मीडिया पर 'Sarpmitra Akash Jadhav' के नाम से सक्रिय था। जांच में खुलासा हुआ है कि वह पिछले एक साल में कम से कम छह बार गांजा ट्रांसपोर्ट कर चुका है। उसकी करीब 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति भी चिन्हित की गई है। इसके अलावा ओडिशा के कालाहांडी जिले से गांजा सप्लाई करने वाले बैकवर्ड लिंक आरोपी रंजन दुर्गा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में थाना कोमाखान में एनडीपीएस एक्ट सहित बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि विवेचना जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, वित्तीय लेन-देन और अवैध संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।

### दिव्यांग श्रेणी में चयनित 13 अभ्यर्थी अचानक हुए लापता,दोबारा बुलाने पर भी नहीं दे रहे ज्वाइनिंग

**रायपुर,30 जनवरी 2026।** छत्तीसगढ़ में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (आरईएओ) पद की भर्ती प्रक्रिया में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। व्यापमं की परीक्षा पास कर नौकरी के लिए चयनित 13 अभ्यर्थी प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान अचानक ही गायब हो गए। इन्हें दूसरी बार भी दस्तावेज जांच के लिए बुलाया गया, लेकिन एक भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ। बता दें कि ऐसी आशंका जताई गई थी कि ये अभ्यर्थी फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर स्वयं को श्रवण बाधित बताकर चयन प्रक्रिया में शामिल हुए थे। मगर अब दोबारा बुलावे के बावजूद अनुपस्थित रहने से यह संदेह और गहरा हो गया है। प्रमाणपत्र जांच से बचने के पीछे फर्जीवाड़े की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि राज्य में अब तक 153 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, जिनमें फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल की गई। इन मामलों में पकड़े गए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण भी ले चुके हैं, वहीं राज्य सरकार ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ के प्रदेश अध्यक्ष बोहित राम चंद्राकर ने कहा कि पहले ही आशंका जताई गई थी कि ये 13 अभ्यर्थी फर्जी प्रमाणपत्रधारी हो सकते हैं। अब उनके सामने न आने से यह बात और स्पष्ट होती जा रही है। उन्होंने मांग की कि इन सभी मामलों की गंभीरता से जांच हो और दोषियों को किसी भी हालत में छोड़ा न जाए।

### रायपुर-कोरबा में बढ़ा जमीनों का रेट...दोनों जिलों में जमीन और मकान की नई सरकारी गाइडलाइन लागू

**रायपुर,30 जनवरी 2026।** छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने रायपुर और कोरबा जिलों के लिए जमीन और मकान की नई सरकारी दरों (गाइडलाइन रेट) को मंजूरी दे दी है। ये संशोधित दरें शुक्रवार 30 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। यानी अब से होने वाली सभी रजिस्ट्रियां नई दरों पर होंगी। महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के तहत शहरी के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की दर में भारी कमी आई है। वहीं रायपुर में फाफाडीह की जमीन सबसे महंगी है। महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय के अनुसार, रायपुर और कोरबा के कलेक्टरों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने मंजूर कर लिए हैं। इसके बाद एनआईसी को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पंजीयन प्रक्रिया में नई दरें तुरंत लागू हो सकें। जानकारी के अनुसार, प्रमुख क्षेत्रों में गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी की गई है। इससे जमीन, मकान और दुकानों की सरकारी कीमतें बढ़ेंगी। गाइडलाइन दरें बढ़ने का सीधा असर स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पर पड़ेगा। यानी पहले की तुलना में अब रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा।

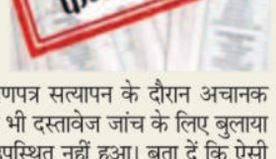

# आधुनिक घोटुल नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ेगा : सीएम साय

**रायपुर, 30 जनवरी 2026।** मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने दो दिवसीय नारायणपुर प्रवास के दौरान 'गढ़बेंगाल घोटुल' पहुंचकर बस्तर की गौरवशाली परंपराओं और लोक-संस्कृति के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इस मौके पर पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मधुर ध्वनि और ग्रामीणों के आत्मीय स्वागत के बीच मुख्यमंत्री साय स्वयं लोक-रंग में रंगे नजर आए। मुख्यमंत्री साय ने घोटुल की अनूठी स्थापत्य कला का अवलोकन किया और बस्तर की विभूतियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि घोटुल प्राचीन काल से ही आदिवासी समाज के लिए शैक्षणिक एवं संस्कार केंद्र रहा है। चेंदु पार्क के समीप स्थित यह आधुनिक घोटुल न केवल नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ेगा, बल्कि देश-दुनिया के पर्यटकों को भी आदिवासी जीवनशैली और सामाजिक व्यवस्था से परिचित कराने का सशक्त माध्यम बनेगा। गढ़बेंगाल का यह घोटुल हमारी गौरवशाली विरासत को सहेजने का प्रतीक है। हमारी सरकार बस्तर की इस अनूठी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री साय ने घोटुल परिसर के लेय्योर एवं लेयोस्क कुरमाः युवाओं और युवतियों के लिए निर्मित कक्षों के साथ ही बिडार कुरमाः पारंपरिक वेशभूषा, प्राचीन वाद्ययंत्र एवं सांस्कृतिक सामग्रियों का संग्रह का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों की आग्रह पर मुख्यमंत्री साय ने सगा कुरमा में बस्तर के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेकर क्षेत्र की खान-पान संस्कृति का सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के भोजन में विशेष रूप से भोजन गाटो-भात,कोदो-भात,उड़िद दार, हिरुवा दार, जीरा भाजी,कनकी पेज, भाजी घिरोल फुल,चाटी भाजी,कांदा भाजी, मुनगा भाजी, इमली आमट,मड़िया पेज,टमाटर चटनी,चिला रोटी,रागी कुरमा, रागी केक, रागी लड्डू, रागी जलेबी परोसा गया। इस दौरान वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा,छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, पद्मपंडीराम मंडावी, लोककलाकार बुटलू राम,वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्रीमती संध्या पवार ने साथ बैठकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने इस प्रवास को केवल एक औपचारिक दौरा न रखते हुए इसे एक आत्मीय मिलन का रूप दिया। क्षेत्र की महान प्रतिभाओं - वैद्यराज पद्महेमचंद मांझी, पद्मपंडीराम मंडावी और सुप्रसिद्ध लोक-कलाकार बुटलू राम से भेंट कर उनका सम्मान किया।

### इको-फ्रेंडली घोटुल

वन विभाग और पद्मपंडीराम मंडावी के मार्गदर्शन में निर्मित यह घोटुल पूर्णतः इको-फ्रेंडली (लकड़ी, मिट्टी और बांस) सामग्री से बना है। मुख्यमंत्री ने घोटुल के खंभों पर की गई बारीक नक्काशी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की, जिसे स्वयं पद्मपंडीराम मंडावी ने उकेरा है। जिसमें नक्काशी, सांस्कृतिक जुड़ाव, विरासत का संरक्षण का प्रभावी प्रयास किया गया है।

### छत्तीसगढ़ का यह नेशनल हाईवे 130सी होगा बंद,सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश...

**रायपुर,30 जनवरी 2026।** सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उड़ीसा के लगभग 10 जिले व छत्तीसगढ़ के कई जिले इससे स्पष्ट रूप से प्रभावित रहेंगे और यहां के निवासी अब चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल वन्य जीव के संरक्षण संवर्धन के दृष्टिकोण से टाइगर प्रोजेक्ट इलाके के कोर एरिया में शाम 6:00 से सुबह 6:00 तक विभिन्न आवागमणों पर रोक लगाते हुए केवल एंबुलेंस आदि इमरजेंसी सेवा के वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है। जिसकी जद में नेशनल हाईवे 130सी भी आ रहा है। यह रास्ता रायपुर, गरियाबंद व उड़ीसा को जोड़ता है। जहां प्रतिदिन सैकड़ों-सैकड़ों यात्री वाहन व माल वाहन के साथ निजी वाहन का आवागमन होता है। गरियाबंद जिले के देवभोग और आगे उड़ीसा के कई जिलों को छत्तीसगढ़ और रायपुर से जोड़ने वाली मुख्य नेशनल हाईवे 130 (सी) भी कोर एरिया से होकर गुजरती है। ऐसे में आदेश के परिपालन में उक्त नेशनल हाईवे पर तौरेंगा से इंदागांव में लगे बैरियर को बंद करने के शासकीय निर्देशन के बाद इलाके के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इतना ही नहीं गरियाबंद और धमतरी जिले के उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के कोर एरिया में आने वाले 50 से अधिक छोटे ग्रामीण मार्गो पर भी आवागमन बंद किया जाना है। गरियाबंद जिला में तौरेंगा बेरियर,जुगाड़ बेरियर, जांगड़ा बेरियर,बम्हनीझोला बेरियर, इंदागांव बेरियर, गरिबा बेरियर शाम 06:00 पीएम से सुबह 06:00एएम तक बंद रखा जायेगा। साथ ही धमतरी जिले के भी दर्जनों बैरियर बंद किए जाएंगे।

# राज्यसभा चुनाव विवाद...सरोज पांडेय पर गलत जानकारी देने का आरोप,याचिकाकर्ता के गवाहों की गवाही पूरी

**रायपुर,30 जनवरी 2026।** साल 2018 में हुए राज्यसभा चुनाव से जुड़े विवाद में भाजपा नेत्री और पूर्व सांसद सरोज पांडेय के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। कांग्रेस उम्मीदवार लेखराम साहू की ओर से पेश किए गए सभी नौ गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। अब मामले में सरोज पांडेय और उनके समर्थकों की गवाही दर्ज की जाएगी। मार्च 2018 में छत्तीसगढ़ की एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने सरोज पांडेय और कांग्रेस ने लेखराम साहू को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने सरोज पांडेय के नामांकन पत्र और शपथ पत्र पर आपत्ति जताई थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने कई अहम जानकारियां छिपाईं। हालांकि, तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया था। बाद में मामला केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्यपाल तक पहुंचा, लेकिन मतदान कराया गया और सरोज पांडेय को विजयी घोषित किया गया।

### चुनाव याचिका के आधार

परिणाम घोषित होने के बाद लेखराम साहू ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की। याचिका में शपथ पत्र में गलत जानकारी देने और कथित रूप से अपात्र विधायकों को मतदान की अनुमति दिए जाने को आधार बनाया गया है। यह मामला लंबे समय से लंबित है और इस पर नियमित सुनवाई हो रही है।

### 18 विधायकों के मतदान पर उठे सवाल

याचिका में कांग्रेस और लेखराम साहू की ओर से आरोप लगाया गया था कि भाजपा के 11 विधायक संसदीय सचिव और 7 विधायक निगम-मंडलों में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के कारण लाभ का पद धारण कर रहे थे। इसी आधार पर इन 18 विधायकों को मतदान से रोकने की मांग की गई थी, लेकिन उस समय निर्वाचन अधिकारी ने दोनों आपत्तियों को नामंजूर कर दिया था।

### अब बचाव पक्ष की बारी

सुनवाई के दौरान विधानसभा के तत्कालीन महासचिव चंद्रशेखर गंगराड़े की गवाही दर्ज की गई, जिसके साथ ही याचिकाकर्ता पक्ष के सभी नौ गवाहों की गवाही पूरी हो गई। सरोज पांडेय की ओर से उनके अधिवक्ता ने शपथ पत्र दाखिल करने के लिए अदालत से दो सप्ताह का समय मांगा गया है जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब अगली सुनवाई में सरोज पांडेय और उनके पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)